● वर्ष-6
● अंक-99
रायपुर, शनिवार
21 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> भारत में खेती को बदल...

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विवादः सुको का अलग सुनवाई से इंकार, कहा- पांच जजों की बेंच करेगी विचार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीजेआई) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। दरअसल, इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी।

अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने और मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक पीठ ने कहा कि रीकॉल (वापसी) आवेदन, और साथ ही रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच रिकॉल एप्लीकेशन (फैसले को वापस लेने की अर्जी) पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने वह स्प्लिट



वर्डिक्ट (बंटा हुआ फैसला) दिया था। भूषण ने कहा कि इस रिकॉल एप्लीकेशन को उसी मूल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने 23 सितंबर को यह स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों का टकराव) की स्थिति है, इसलिए फैसले को वापस लेने की इस अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।

जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच (मामले को आगे भेजने वाली बेंच) इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप के कारण खुद उस रेफरेंस ऑर्डर को ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।

यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए उस स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं।

एससीओ सभ्यता संवादः सिंधु जल संधि पर भारत बोला- रुख में कोई बदलाव नही

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया है। यह बयान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के दिल्ली में स्ष्ठह सभ्यता संवाद मंच में भाग लेने के दौरान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पुराना किला में इस तीन दिवसीय मंच का उद्घाटन किया। मलिक शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को मंच के उद्घाटन दिवस में शामिल हुए। भारत ने 28 अक्तूबर को सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजा था। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7-10 मई की सैन्य शत्रुता के बाद यह पहली बार था जब भारत ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आईडब्ल्यूटी पर भारत की स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने मलिक की भागीदारी को दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार के अवसर के रूप में देखा। मलिक ने संवाददाताओं से बातचीत में संस्कृति की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया।

भारत 20-22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पहले एससीओ सभ्यता संवाद की मेजबानी कर रहा है। यह एससीओ ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। इसके लिए पाकिस्तान सहित सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजे गए थे। एससीओ के पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों को भी इस संवाद में आमंत्रित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं।

सिंधु जल संधि पर भारत का रुख- भारत ने 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह निलंबन पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों में से एक था। यह कदम पिछले साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया था। उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईडब्ल्यूटी से संबंधित भारत का रुख अटल है। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इसकी स्थापना की थी।



न नौकरी बढ़ी, न सैलरीः मोदी पर राहुल का तंज, बोले- ये आपका कबूलनामा; भक्तों से बजवाएं ताली और थाली

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने को लेकर सवाल करने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का उद्योगपतियों से यह पूछना कि टैक्स में राहत देने के बावजूद उन्होंने न तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और न ही नौकरियां दीं, उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, बल्कि खुद सरकार का कबूलनामा है।



राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं वाले बयान पर भी तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। राहुल ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दी गईं, लेकिन इनसे कितने रोजगार पैदा हुए, इसका जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि रोजगार देने वाले छोटे व्यापारी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नोटबंदी और गलत तरीके से लागू जीएसटी के कारण प्रभावित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी कमजोर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एकाधिकार से नौकरियां पैदा नहीं होतीं, बल्कि महंगाई बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों से कहे गए आप करो, हम देख लेंगे वाले बयान पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे कारोबारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को निराश किया है।

बातचीत से सुलझेंगे मुद्देः एससीओ के सभ्यता संवाद मंच में शामिल हुए पाकिस्तानी मंत्री; आतंकवाद पर क्या बोले?

नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पहले सभ्यता संवाद मंच में पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। ऐसे में सबसे आसान रास्ता उन मुद्दों पर बात करना है, जो सभी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, हमें संस्कृति और सभ्यताओं पर बात करनी चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि इन सभ्यताओं ने हम सभी को किस तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं एससीओ का बहुत आभारी हूं कि वह ऐसे मंच आयोजित कर रहा है। ये मंच क्षेत्र के सभी देशों को एक साथ आने का मौका देते हैं। यहां ऐसे विचारों पर बात हो सकती है, जो सीमाओं से आगे जाते हैं।



पाकिस्तानी मंत्री से भारत की सीमा पार आतंकवाद को लेकर चिंता के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कल जब मैं अपना बयान दूंगा, तब इस पर काफी बातचीत होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच सभ्यताओं के पुराने संबंधों को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर मलिक ने कहा, मुझे लगता है कि संवाद अलग-अलग पक्षों के बीच होता है। जहां सब एक जैसे हों, वहां संवाद की जरूरत नहीं होती। वहां सिर्फ एकतरफा बात होती है। संवाद विविधता के बारे में होता है। उन्होंने कहा, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच अगर आप खुदाई में मिले पुराने अवशेषों को देखेंगे, तो आपको वहां भी संवाद के प्रमाण मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी और स्वागत योग्य पहल है।

पाकिस्तानी मंत्री से पूछा गया कि क्या पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार होगा? इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सभी देशों के संबंध बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले से म्यांमार को झटका, भारत बोला- शरणार्थियों की वापसी का समर्थन

म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई हिंसा को नरसंहार करार देने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने इस फैसले पर संज्ञान लिया है। साथ ही भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, शीघ्र और स्थायी वापसी का लगातार समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी द्वि-साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईसीजे के ऐतिहासिक फैसले पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने रखाइन राज्य से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का हमेशा समर्थन किया है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इस दिशा में पहले भी कई कदम उठाए हैं। ऑपरेशन इंसानियत के तहत भारत ने पांच चरणों में राहत सामग्री भेजकर बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की मदद की थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है। इसका उद्देश्य विस्थापित लोगों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने में मदद करना है।

ईडी के रडार पर भाजपा सांसदः निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में भेजा समन

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला पंजाब की एक कंपनी से जुड़ा है। आरोप है कि इस कंपनी ने निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। संधू की उम्र 57 साल है। वह मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) भी हैं। यह एक निजी विश्वविद्यालय है। अधिकारियों ने बताया कि संधू को पहली बार 12 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह उस दिन नहीं पहुंचे। अब उन्हें 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

ईडी की शक्तियों पर फिर कानूनी लड़ाईः पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में 2022 के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इस फैसले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बरकरार रखा था। इन शक्तियों के तहत ईडी को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में गिरफ्तारी करने का अधिकार है। संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा तलाशी लेने और सामान जब्त करने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिए गए हैं।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया। मामले में पेश हुए वकीलों ने बेंच से जल्द से जल्द सुनवाई की तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर बेंच ने कहा, हम जनवरी में इसकी सुनवाई कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा, सुनवाई की तारीख की सूचना दी जाएगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

संसद के मानसून सत्रका 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं



नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है, जो अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। इससे पहले वर्ष 2008 में बिना सत्रावसान के 87 दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इस बीच महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बरकरार है। संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है।

विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक लोस सीटों की संख्या न बदले कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए। इस व्यवस्था को विकसित भारत का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल होने तक स्थिर रखा जाना चाहिए।'' उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है।

1962 की हार पर माफी मांगे कांग्रेसः रिजिजू

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की समझौता करने वाले प्रधानमंत्री वाली टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस से चार सवाल पूछते हुए कहा कि पार्टी को 1962 के युद्ध में मिली हार के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीब देश क्यों बना रहा और देश की अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया? किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस से चार सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को चार सवालों के जवाब देने चाहिए। रिजिजू की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चीन में गुरुवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई त्रिपक्षीय बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने इन तीनों नेताओं की बैठक की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा था, अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते।

मणिपुरः जहरीली शराब से 13 की मौत

इंफाल। मणिपुर के चंदेल जिले में 18 नवंबर को जहरीली शराब पीने के बाद से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। मरीज मुख्य रूप से पहाड़ी जिले के चकपिकारोंग और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। इन्हें इंफाल के कई अस्पतालों - जैसे जेएनआईएमएस, आरआईएमएस, शिजा और बबीना - में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, शुक्रवार रात 9 बजे तक 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि जहरीली शराब पीने के कारण मेथनॉल पॉइजनिंग के शक में 346 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार दोपहर शिजा अस्पताल और बबीना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां हालात का जायजा लिया और इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा, मैंने लैम्फेलपट स्थित शिजा अस्पताल और सजीवा स्थित बबीना अस्पताल का दौरा किया। वहां मैंने उन लोगों का हाल जाना, जो चंदेल जिले के चकपिकरोंग इलाके में जहरीली शराब पीने के बाद इलाज करा रहे हैं।

एफबीआई के आपराधिक रिकॉर्ड्स में दूसरी बार लगी सेंध

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा तंत्र को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सबसे महत्वपूर्ण नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर डेटाबेस में सेंधमारी का गंभीर मामला सामने आया है। हाल के महीनों में देश के अपराध रिकॉर्ड को निशाना बनाने वाली यह दूसरी बड़ी साइबर सुरक्षा घटना है। यह हैक ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी प्रशासन बैंकिंग और बुनियादी ढांचा प्रणालियों में आई तकनीकी रुकावटों के बाद सार्वजनिक विश्वास बहाल करने में जुटा हुआ था। नवीनतम सेंधमारी ने एफबीआई के जिस देशव्यापी आपराधिक सूचना डेटाबेस को निशाना बनाया है, वह पूरे अमेरिकी कानून प्रवर्तन तंत्र के लिए जीवन रेखा के समान है। इस डेटाबेस का उपयोग पूरे देश में संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां रोजाना करती हैं। इसमें फरार अपराधियों (भगोड़ों), चोरी की संपत्तियों, अदालती वारंटों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस ब्रीच के चलते संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान में बड़ी बाधा उत्पन्न होने की आशंका है।

पूरी तस्वीर देखने की बजाय एक फोटो पर अटक जाते हैं राहुल गांधी! इसलिए हर बार पिछड़ जाते हैं

नीरज कुमार दुबे

राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ अनौपचारिक बातचीत करते दिखाई दिए थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ बैठे हुए तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। राहुल गांधी को शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि जिस तस्वीर को दिखाकर वह भारत की कूटनीतिक हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरह की तस्वीर साल भर के भीतर दो बार देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी और रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनीं थीं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साथ वाली तस्वीरों पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने प्रतिक्रिया दी थी।

राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ अनौपचारिक बातचीत करते दिखाई दिए थे। इसके बाद सितंबर 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी तीनों नेता एक ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौजूद थे। यानी एक साल के भीतर दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग के साथ ट्रंप की त्रिपक्षीय मुलाकात से महज दो दिन पहले यानि 17 नवंबर को मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्वॉड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ऐसे में राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जिस ट्रंप के साथ पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर दिखाकर वह भारत को वैश्विक कूटनीति से बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रंप उससे ठीक पहले मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच पर मौजूद थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को केवल एक तस्वीर के आधार पर समझने की कोशिश करने के बजाय इन मुलाकातों और वैश्विक मंचों पर भारत की निरंतर मौजूदगी को भी देखना चाहिए।

साथ ही राहुल गांधी को एक्स पर की गयी अपनी पोस्ट पर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं पर भी गौर करना चाहिए। यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में होने से भारत को चीन में हुई बैठक में जगह मिलने की क्या गारंटी थी? जनता पूछ रही है कि क्या केवल कांग्रेस की सरकार होने से अमेरिका, रूस और चीन भारत को अपने बीच बैठा लेते?

एक तस्वीर को नहीं पूरी तस्वीर को देखना चाहिए- देखा जाये तो राहुल गांधी की राजनीति एक तस्वीर के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, जबकि भारत की वैश्विक हैसियत का आकलन करने के लिए पिछले वर्षों में हुए कूटनीतिक बदलावों को देखना जरूरी है। आज भारत की पहचान केवल एक बड़े बाजार या विकासशील अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि वह दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने वाला देश बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग देशों से मिले 35 अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी इसी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भूटान, ब्राजील, नाइजीरिया और कई अन्य देशों ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए हैं।

भारत में सफल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन- बार-बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति की सफलता का ताजा उदाहरण सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा-पत्र स्वीकार किया। सम्मेलन का विषय था- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ऐसे समय में जब दुनिया व्यापारिक तनाव, युद्ध, ऊर्जा संकट और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, भारत ने ब्रिक्स के मंच पर विकासशील देशों के हितों, आर्थिक सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार को प्रमुखता दी। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत ने ब्रिक्स को किसी एक देश या शक्ति के विरुद्ध खड़े होने वाले संगठन के बजाय सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले मंच के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मेलन के दौरान 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा।



अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने महिला ने दी जान देने की कोशिश

उपसरपंच और प्रबंधक पर 50 हजार मांगने का आरोप

जांजगीर चांपा। नवागढ़ ब्लॉक के सिउड गांव धान खरीदी केंद्र के पास शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। महिला के इस कदम के बाद अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक उलटे पांव लौट गए। महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। महिला ने गांव के उपसरपंच और धान खरीदी प्रबंधक के साथ एक अन्य व्यक्ति पर जमीन कब्जा नहीं हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया। सिउड गांव का धान खरीदी केंद्र स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अतिक्रमण हुए मकानों से घिरा हुआ है। वही छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में विजय कुमारी धीवर भी अपनी बेटी के साथ रहती है। 6 माह पहले महिला ने कुछ ईंटों को जोड़कर तीन फीट की जगह पर टीन का छत डालकर छोटा सा घर बनाया और रहने लगी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बाद से धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक राजू और उप सरपंच के साथ, एक अन्य ग्रामीण उसे परेशान कर रहे हैं। उससे जमीन नहीं छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं।

बुधवार को तीनों जेसीबी मशीन लेकर विजय कुमारी धीवर का घर तोड़ने पहुंचे और नवागढ़ तहसीलदार और पुलिस के पहुंचने से पहले महिला से विवाद करने लगे। धान खरीदी केंद्र के आसपास बने कई अवैध मकानों में सिर्फ झोपड़ीनुमा मकान को तोड़ने पहुंचे लोगों के बीच महिला ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया।

विजय कुमारी धीवर के जहर पीने की घटना के बाद आनन फानन में 112 बुलाया गया, तब तक तहसीलदार की टीम भी मौके पर पहुंची और महिला की हालत को देखने के बाद उलटे पांव वापस लौट गई।धान खरीदी केंद्र में एक महिला ने बेजा कब्जा कर रखा है। प्रबंधक और ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे थे। पहले भी महिला को ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया था। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने कुछ सेवन किया है। गांव वाले ही अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला का इलाज जारी है। पंचायत स्तर पर ही कार्रवाई हो रही थी -उमाशंकर जायसवाल, तहसीलदार नवागढ़

महिला द्वारा जहर सेवन करने की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच कर महिला का बयान दर्ज किया है, जिसमे महिला ने तीन लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और घर तोड़ने की नियत से मशीन और अधिकारियों को बुलाने के कारण डर कर जहर पीने की शिकायत की है, इस मामले में महिला के स्वास्थ्य सुधार होने पर विस्तृत जानकारी लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

जशपुर को दो रेल लाइनों की सौगात, 1970 के दशक से चली आ रही मांग पूरी होने की ओर



जशपुरनगर। दशकों से रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने जिले से जुड़ी दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाया है। एक ओर झारखंड के लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना में शामिल कर राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक 218 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को भी स्वीकृति मिल गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने दोनों रेल परियोजनाओं को जशपुरवासियों के लिए डबल इंजन सरकार का दोहरा उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि जिले को एक के बाद एक दो रेल परियोजनाओं की सौगात मिलना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से जशपुर में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। इन परियोजनाओं से आने वाले समय में जिले की तस्वीर बदलने की संभावनाएं हैं। दरअसल, जशपुरवासी 1970 के दशक से लोहरदगा-कोरबा रेल लाइन की मांग करते आ रहे हैं। रेल सुविधा के अभाव में जिले के लोगों को आज भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में लोहरदगा से धरमजयगढ़ रेल लाइन और सरडेगा से अंबिकापुर रेल लाइन को मिली प्राथमिकता जिले के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरडेगा से पत्थलगांव तक रेल लाइन पहुंचने पर इसका संपर्क लोहरदगा-धरमजयगढ़ रेल परियोजना से जोड़ने की संभावनाएं भी बनेंगी। इससे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच रेल संपर्क का एक व्यापक नेटवर्क तैयार हो सकेगा।सरडेगा से अंबिकापुर तक प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लंबाई 218 किलोमीटर है। सर्वेक्षण के अनुसार सरडेगा से पत्थलगांव तक 128 किलोमीटर और पत्थलगांव से अंबिकापुर तक 90 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। ओडिशा में सरडेगा, बरपाली रोड, टांगरपाली, गोटाबंधा, बेलमुंडा और बैसकीमुड़ा स्टेशन प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ में खम्हार, बोगुडेवा, पत्थलगांव, करमीटिकरा, उलकिया, सीतापुर, कपाटबहरी, बतौली, कालीपुर, नवापारा, कतकालो, मणिपुर और अंबिकापुर में स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है।

नक्सलियों का डंप बरामद

विस्फोटक सामग्री समेत भारी मात्रा में उपयोगी सामान जब्त



कोंडागांव। जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पित माओवादियों की निशानदेही पर थाना पुंगारपाल क्षेत्र के ग्राम बेड़मा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप सामान को बरामद किया गया।

नक्सल सेल, डीआरजी/बस्तर फाइटर्स एवं बीडीएस की संयुक्त टीम ने ग्राम हांडापाल, देवगढ़, बेड़मा एवं आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान बेड़मा के जंगल में सुरक्षित कॉर्डन एवं डी-माइनिंग कार्रवाई करते हुए माओवादियों के डंप किए गए सामान के दो अलग-अलग स्थानों से विस्फोटक सामग्री एवं अन्य उपयोगी सामान बरामद किया गया।बरामद सामग्री में 01 हैंड ग्रेनेड, 02 जिलेटिन रॉड, लगभग 25 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 04 बंडल इलेक्ट्रिक वायर (लगभग 200 मीटर), वॉकी-टॉकी चार्जर, 03 किलो सल्फर, 04 किलो सोडियम नाइट्रेट, 14 टिफिन, मल्टीमीटर, लगभग 50 मीटर रस्सी, 07 सिरिंज, 01 बड़ा टिन का पेटी, 04 बैडमिंटन रैकेट, 03 रिंग रबर एवं 11 बैटरी सेट शामिल हैं।

पुलिस द्वारा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जारी है। संयुक्त सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री को बरामद कर नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई की गई है।

जांजगीर चांपा हनी ट्रैप: 60 हजार रुपये और सोने की अंगूठी की लूट



जांजगीर चांपा। सोशल मीडिया के जरिए युवक से दोस्ती कर हनी ट्रैप में फंसाने और मिलने के बहाने बुलाकर साथियों के साथ चाकू की नोक पर मारपीट और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश जांजगीर पुलिस ने किया है। एक महिला के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से ?30,000 नकद, मोबाइल फोन और 2 बाइक जब्त की है। रायगढ़ जिले के रहने वाले मनीष वर्मा ने रायगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से उसकी दोस्ती रायगढ़ की ही रहने वाली एक युवती से हुआ। उनके बीच बातचीत होती थी। इसी दौरान युवती ने मनीष को चांपा मिलने के लिए बुलाया। 4 नवंबर को मनीष कार में अपने एक दोस्त के साथ युवती से मिलने पहुंचा। युवती के कहने पर वह अपने दोस्त को ढाबा के पास छोड़ कर फिर लड़की से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसका कैश और सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए। हनी ट्रैप का मैटर है। रायगढ़ जिले में एक लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध था, दोनों रायगढ़ के ही रहने वाले हैं। लड़की ने एक दिन युवक को चांपा के एक रेस्टोरेंट में बुलाया, वहां पहले से ही कुछ लड़के थे। उन्होंने प्रार्थी युवक के साथ मारपीट की और 60 हजार रुपये यूपीआई से ले लिए। सोने की अंगूठी भी ले ली। आरोपियों के साथ लड़की भी चली गई। जिसके बाद युवक को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी युवती और अन्य 6 को गिरफ्तार कर लिया -विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चांपा प्रार्थी की शिकायत को रायगढ़ पुलिस ने शून्य में कायम कर जांजगीर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट सौपी। जिस पर थाना कोतवाली जांजगीर में अपराध क्रमांक 917/2026, धारा 115(2), 308 (2), 111(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल महिला के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी:

अमित राठौर, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 12, जांजगीर, रवि झलरिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, जांजगीर, किशन कर्ष, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम महुदा, थाना चांपा, हाल खडफड़ी पारा वार्ड क्रमांक 21, जांजगीर, कुनाल पाण्डेय, उम्र 20 वर्ष, निवासी लिंक रोड शंकर विहार कॉलोनी, जांजगीर, हाल भोजपुर मिशन हॉस्पिटल, थाना चांपा, मुकेश कश्यप उर्फ छोटू, उम्र 19 वर्ष, निवासी जोबी (जर्वे च), थाना जांजगीर, एक युवती, रायगढ़ निवासी, जांजगीर चांपा एसपी की आम लोगों से अपील, जांजगीर चांपा एसपी ने सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती एवं बातचीत करते समय सतर्क रहने की अपील की है।

नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में 2.27 करोड़ की गड़बड़ी



नारायणपुर। स्वास्थ्य विभाग में 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये के वित्तीय अंतर के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पांच सदस्यीय टीम की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर सील करने की कार्रवाई की। जांच समिति के गठन से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की यह कवायद मामले की जांच के लिहाज से अहम मानी जा रही है नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में ष्टस्क्रमद की राशि से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड में 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये का अंतर सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड में सामने आए इस अंतर को लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। अब मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारी के चेम्बर को सील करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक निलंबित सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज परते के चेम्बर को सील करने का निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि वहां मौजूद फाइलों, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके। जांच समिति के गठन और जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले किसी भी दस्तावेज के गायब होने, उसमें बदलाव होने या छेड़छाड़ की आशंका को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीआर कुंवर सहित पांच सदस्यीय टीम की मौजूदगी में चेम्बर सील करने की कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले पंचनामा तैयार किया ताकि सीलिंग की पूरी प्रक्रिया विधिवत रिकॉर्ड में दर्ज रहे और बाद में जांच के दौरान दस्तावेजों की स्थिति को लेकर कोई विवाद न हो। विभागीय स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को वित्तीय अनियमितता के मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि ऑडिट के दौरान संबंधित वित्तीय योजनाओं के खर्च से जुड़े लेजर, कैशबुक, बिल और वाउचर जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात सामने आई थी।

इसके बाद नोटिस जारी किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

बोलेरो ने थार समेत कई कारों को मारी टक्कर



कोरबा। कोरबा से हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने होटल के सामने खड़ी कारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कोई जनहानी तो नहीं हुई, लेकिन कई वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हो गए हैं। वही पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

यह घटना गुरूवार की रात दीपका थाना क्षेत्र में हुई है। गेवरा दीपका के कटघोरा रोड स्थित सिंह रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग में खड़ी कारों को बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मारुति कार, थार सहित कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

रेस्टोरेंट संचालक अक्षय सिंह के मुताबिक, बजरंग चौक दीपका की ओर से आ रही बोलेरो में चालक समेत तीन लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बोलेरो स्थ्ष्टरु में नियोजित है और चालक विजयनगर का रहने वाला है।

घटना की जानकारी मिलते ही दीपका थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु कर दी है। वहीं यह घटना वहां लगे ष्टष्टङ्कङ्क में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बोलेरो तेज रफ्तार में है और अनियंत्रित होकर रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग में खड़ी कारों को टक्कर मार देती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शराब का सुरूर ऐसा कि थाना प्रभारी से भीड़ गया युवक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बदमाशों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। गुरुवार रात सिम्स अस्पताल के सामने युवक पहले राहगीरों को परेशान करता रहा। सूचना पर सिविल लाइन थाना प्रभारी पहुंचे और समाझाइश देने लगे। इस दौरान युवक ने टीआई से बदसलूकी करते हुए हाथापाई और धक्का-मुक्की पर उतारू हो गया। इस घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, सिम्स अस्पताल के सामने गुरुवार की रात युवक नशे की हालत में राहगीरों को परेशान कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाइश देने लगे। बदमाश के हौंसले इतने बुलंद थे कि वह थाना प्रभारी के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और हाथापाई की कोशिश तक पहुंच गया। सामने आए वीडियो में आरोपी युवक ने थाना प्रभारी के समझाइश पर भड़क गया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हाथापाई की कोशिश और धक्का-मुक्की करने लगा।

अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारी तो महिला ने पी लिया जहर

जांजगीर-चांपा। जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही खरीदी केंद्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नवागढ़ ब्लॉक के सिउड़ गांव में धान खरीदी केंद्र के पास स्थित शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने एक महिला ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद तहसीलदार, पंचायत प्रतिनिधि और धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक को कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा। महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं, महिला ने गांव के उपसरपंच, धान खरीदी केंद्र प्रबंधक और एक अन्य व्यक्ति पर अतिक्रमण नहीं हटाने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल, सिउड गांव का धान खरीदी केंद्र स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अतिक्रमण हुए मकानों से घिरा हुआ है। वही छोटे से झोपडी नुमा मकान में विजय कुमारी धीवर भी अपनी बेटी के साथ रहती थी। 6 माह पहले उसने कुछ ईंटो को रचकर तीन फ़ीट में ही टीन का छत बनाया था और उसमें रह रही थी।

देवभोग से बड़ी मात्रा में ओडिशा से पहुंच रहा अवैध धान

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी योजना शुरू होते ही देवभोग और अमलीपदर में ओडिशा के तीन जिलों के सीमाओं से भारी मात्रा में धान का खेप पहुंचना शुरू हो जाता है। दरअसल इस इलाके में धान की औसत उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी। बोनस के लालच में किसान बिचौलिए से धान खरीद कर इस अंतर को पूरी करते थे। सरकार द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित पूरी बोनस देने का ऐलान कर दिया गया है। न्यूनतम एक किलो तक की बिक्री को आधार माना गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी किसान ओडिशा के धान मंगा रहे। बताया जा रहा है कि ओडिशा से संपर्क रखने वाले बिचौलिए इस बार भी वहां की अतिरिक्त धान उपज खपाने के लिए किसानों को अपने झांसे में ले रहे हैं। हालांकि जागरूक किसान इस योजना को समझ चुके हैं, लेकिन जिन किसानों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें बिचौलिए अपने जाल में फंसा रहे हैं। यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों में अब भी रोजाना सैकड़ों क्विंटल ओडिशा का धान पहुंच रहा है।

बारिश में धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें : कलेक्टर

महासमुंद। मौसम में बदलाव और संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान को बारिश, तेज हवा, जमीन की नमी और जलभराव से सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी केंद्रों में पर्याप्त कैप कवर, पन्नी एवं तिरपाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि खुले में रखे धान के सभी स्टैक को मजबूत रस्सियों से अच्छी तरह बांधा जाए, ताकि तेज हवाओं के कारण तिरपाल एवं कैप कवर उडऩे की स्थिति निर्मित न हो। जमीन से आने वाले पानी और नमी से धान को बचाने के लिए पर्याप्त डनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों के फड़ के चारों ओर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने तथा नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में केंद्रों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए।

यूपी के चुनावी रण में छग की महिला शक्ति का पदार्पण

बिलासपुर। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2027 की सियासी सरगर्मी अभी से तेज होने लगी है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियों को गति दे दी है। इसी रणनीति के तहत अब महिला मोर्चा को भी चुनावी अभियान के केंद्र में लाने की तैयारी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की करीब 100 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टीम प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के नेतृत्व में सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हुई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ की महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, संगठनात्मक समन्वय, महिला मतदाताओं से संवाद और बूथ स्तर पर सक्रियता जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के बाद प्रशिक्षित पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश की अलग-अलग विधानसभा सीटों में विस्तारक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

भाजपा किसान मोर्चा ने बताया ऐतिहासिक और किसान हितैषी फैसला



एमसीबी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब ऐसे किसान जो किसी कारणवश प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की निर्धारित मात्रा के बराबर उत्पादन नहीं कर पाते, उन्हें भी निर्धारित अंतर राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को भाजपा किसान मोर्चा ने ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताते हुए किसानों के सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

इसी विषय को लेकर एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बृजलाल राठौर ने प्रेसवार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने धान खरीदी के दौरान किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी, अब कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऐसे किसानों को भी अंतर राशि का लाभ दिया जाएगा, जो अपनी उपज कम होने के कारण 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा नहीं बेच पाते। बृजलाल राठौर ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं, जिनकी जमीन की उत्पादन क्षमता प्राकृतिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की पैदावार नहीं हो पाती। ऐसे किसान यदि प्रति एकड़ 10 क्विंटल या उससे कम धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने वाली राशि के अनुरूप 13,839 रुपये की अंतर राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।

इससे कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी सरकार की किसान हितैषी नीति का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा पूरी करने को लेकर कई तरह की परिस्थितियां निर्मित होती थीं। कुछ मामलों में बिचौलियों की सक्रियता और धान की मात्रा पूरी करने के लिए होने वाली गतिविधियों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार परिवहन, धान की व्यवस्था और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं।

यहां तक कि कुछ परिस्थितियों में किसानों को संदेह की दृष्टि से भी देखा जाने लगता था। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस नए निर्णय से ऐसी परिस्थितियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

किसानों के खाते में सीधे अंतर राशि पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी और वास्तविक किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों की भी रक्षा होगी।

भाजपा किसान मोर्चा के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए फैसले ले रही है।

किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके परिश्रम से ही प्रदेश की कृषि व्यवस्था मजबूत होती है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।

सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा कर खरीदा प्लॉट, अब वैधता पर सवाल



खैरागढ़। सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। खैरागढ़ के एडवर्ड पार्क जमीन विवाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम 1200 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा। जमीन की खसरा नकल मिला, नामांतरण हुआ, रजिस्ट्री कराई और नगर पालिका से मकान बनाने की अनुमति भी मिल गई। इसके बाद उसने अपनी जमा-पूंजी लगाकर मकान बनवा लिया। लेकिन अब उसी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आने के बाद उसके अपने मकान की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले को लेकर जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने प्रेसवार्ता कर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन खरीदते समय सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध थे। किसी भी स्तर पर उन्हें यह नहीं बताया गया कि जमीन की स्थिति विवादित है, या वहां प्लॉटिंग में नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब जब प्रशासनिक जांच में एडवर्ड पार्क की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के तथ्य सामने आए हैं, तो वे अपने ही मकान की वैधता को लेकर परेशान हैं। झा का सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन की स्थिति संदिग्ध थी, तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल और नामांतरण कैसे किया? रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और नगर पालिका ने मकान बनाने की अनुमति किस आधार पर दे दी? यदि जमीन में गड़बड़ी थी तो सरकारी विभागों ने समय रहते खरीदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? दरअसल, एडवर्ड पार्क विवाद में सिविल लाइन स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 114 और 115 की जांच के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक करीब 85,627 वर्गफीट जमीन को बिना स्वीकृत ले-आउट और जरूरी नजूल अनापत्ति प्रमाणपत्र के 22 भूखंडों में बांटकर बेचा गया। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भी संबंधित जमीन के लिए विकास अनुमति या अभिमत जारी नहीं होने की जानकारी सामने आई है।

संक्षिप्त समाचार

सीएम योगी की माता का निधन
मुख्यमंत्री साय ने दी श्रद्धांजलि



रायपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बीमारी के कारण 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने शोक जताया और श्रद्धांजलि व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीएम योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। एक पुत्र के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के स्नेह और आशीष का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता। दु:ख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं योगी और उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को इस अपार दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम् शांति! छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद एवं हृदयविदारक है। प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीधाम में स्थान तथा शोकाकुल पूज्य महाराज जी एवं समस्त परिवारजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम् शांति।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव बदले, जितेंद्र बघेल और हरनाम को जिम्मेदारी

रायपुर। कांग्रेस ने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने 81 सचिवों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों में बदलाव की सूची जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव भी बदल दिए गए हैं। अब जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले यह जिम्मेदारी विजय जांगिड और एसए संपत कुमार संभाल रहे थे। वहीं, जरिता लैतफलांग को छत्तीसगढ़ के प्रभार से हटाकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों को लेकर सूची जारी की है। पार्टी के मुताबिक, सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को दूसरे राज्यों में भी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है।

नर्सिंग की रिक्त सीटों के लिए दूसरे और तीसरे चरण की संयुक्त काउंसिलिंग शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दूसरे और तीसरे (मॉप-अप राउन्ड) चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें शामिल हैं। इस चरण के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी संस्था और विषय का दोबारा चयन कर सकेंगे। संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने विकल्प दोबारा भरकर लॉक करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रवेश ले चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन का विकल्प भी मिलेगा। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पंजीयन और संस्था का चयन कर सकेंगे। यह प्रावधान केवल बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा। समिति ने अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश संबंधी आगामी जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट www.cgdme.in नियमित रूप से देखने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध कराया गया है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं । आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा में जमा किए जा सकेंगे। सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों एवं संभागों में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए मान्य होगा।

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार

राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया स समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) श्री सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।

स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स - 2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस



उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी।

इस अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अरुण कुमार ध्रुव तथा नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के अध्यक्ष श्री राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।

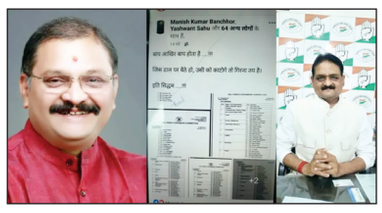
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से शहरी आजीविका संवर्धन, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन और छोटे व्यवसायियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति मामला

'बाप तो आखिर बाप होता है'- पूर्व सीएम बघेल के ओएसडी के पोस्ट से बखेड़ा

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति की है। फेरबदल के तहत भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को एआईसीसी सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा विजय जांगिड समेत कुल 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर के सोशल मीडिया पोस्ट से बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'बाप तो आखिर बाप होता है। जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटोगे तो गिरना तय है। इति सिद्धम।'

दरअसल मनीष बंछोर का पोस्ट विधायक देवेंद्र यादव की ओर इशारा कर रहा है। बता दें कि भूपेश बघेल



और देवेंद्र यादव के बीच दूरी हमेशा चर्चा का विषय रहा है। अब मनीष बंछोर के इस पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है। भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने इस फेरबदल को कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे इंटरनल मामला बताया है। देवेंद्र यादव समेत 25 लोगों को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाने पर सांसद पांडेय ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि द्वेष, कलह, गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। अपनी ढपली अपना राग, अपना नगाड़ा अपना फाग, भूपेश, ताम्रध्वज एक ही डाल पर, यादव हुए डाउनफॉल पर। मेरी बिल्ली मेरी से म्याऊं, तेरी पुंगी बना भिलाई में बजाऊं। तीन प्रभारी सचिवों की छुट्टी, पियो पांच सौ पचपन मुंगली घुट्टी।

भाजपा सांसद संतोष पांडेय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की नियुक्ति हमारा अपना इंटरनल मामला है। संतोष पांडे के पास अपनी सरकार के लिए बोलने को कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार में धान खरीदी से किसान परेशान हैं। पटवारियों की हड़ताल जारी है। डीएड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इन विषयों पर संतोष पांडे पल्ला झाड़ते हैं। कांग्रेस की नियुक्तियों पर शायरी कर पहेलिया बना रहे हैं।

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी

■ दावेदारों में पूर्व महापौर, उनकी पत्नियों से लेकर बड़े नेताओं के करीबी तक शामिल



रायपुर। प्रदेश के चार नगर निगम भिलाई, बीरगांव, रिसाली और भिलाई-चरौदा के अलावा पांच नगर पालिका और आठ नगर पंचायतों सहित कुल 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद एक या दो दिसंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच लोगों की निगाहें मुख्यत: चार नगरीय निकायों पर लगी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा महापौर पद को लेकर है।

महापौर पद के लिए मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा जोहार छत्तीसगढ़ के भी नेता सक्रिय हैं। दावेदारों में जो नाम उभरकर सामने आ रहे हैं, उनमें कई पूर्व महापौर, उनकी पत्नियां के अलावा बड़े नेताओं के नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं।

प्रदेश में जिन नगरीय निकायों का चुनाव होना है, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा भिलाई नगर निगम की है। भिलाई नगर निगम में महापौर का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए कांग्रेस के अनेक दावेदार हैं, इनमें वर्तमान महापौर नीरज पाल के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चन्द्राकर, वर्तमान निगम सभापति बंटी साहू, जोन अध्यक्ष व पार्षद भूपेन्द्र यादव, और प्रदेश कांग्रेस सचिव अतुलचन्द साहू शामिल हैं।

वहीं भाजपा की ओर से महापौर पद के दावेदारों में भिलाई निगम में विधायक रिकेश सेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष पुरषोत्तम देवांगन, पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा के अलावा जिला भाजपा संयोजक आरटीआई प्रकोष्ठ मदन सेन की भी दावेदारी बताई जा रही है।

भिलाई निगम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा सांसद विजय बघेल के दबदबे वाले भिलाई-चरौदा नगर निगम चर्चा में है। इस निगम से महापौर पद केलिए कांग्रेस से सुजीत बघेल का नाम फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि केवल उनकी ओर से ही आवेदन दिया गया है। वहीं सभापति कृष्णा चन्द्राकर ने स्वास्थ्यगत कारणों से आवेदन नहीं दिया है।

चक्रवात अकवान से फसल नुकसान पर सीएम साय का बड़ा बयान

किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं सर्वे के बाद मिलेगा मुआवजा

रायपुर। चक्रवाती तूफान अकवान के चलते आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इस चक्रवात से फसलों को नुकसान की आशंका के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को राहत का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार फसल नुकसान की स्थिति में प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि चक्रवात से फसलों को होने वाले



संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। यदि तूफान के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है तो संबंधित क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को फसल बीमा और मुआवजा संबंधी प्रावधानों के तहत राहत उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम साय ने कहा कि इससे पहले भी चक्रवात के कारण प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचा था। उस दौरान भी सरकार ने नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की थी। इस बार भी फसल क्षति का आकलन कराया जाएगा और नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से चक्रवात के संभावित असर को लेकर चिंतित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पुलिस जांच के दौरान रोके जाने पर बिफरा पिकअप चालक

■ गाली-गलौच करते हुए टीआई पर चढ़ा दी गाड़ी, एफआईआर दर्ज



रायपुर। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के दौरान राजधानी रायपुर में ऐसी घटना घटी, जिसकी चर्चा हो रही है। जांच के दौरान टाटा एस वाहन चालक ने गाली-गलौज करते हुए रास्ते से नहीं हटने पर ट्रैफिक थाना प्रभारी को ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना में जहां घायल टीआई का अस्पताल में उपचार किया गया, वहीं आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 16 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस की टीम शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच और कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान यातायात थाना नया बस स्टैंड भाठागांव के निरीक्षक एवं प्रभारी नवल किशोर कश्यप अपनी टीम के साथ कुशालपुर चौक से भाठागांव की ओर आने वाली सर्विस रोड पर चल रही वाहनों की जांच कर रहे थे। टीम में प्रधान आरक्षक अभयराव, आरक्षक मनोज सावड़े सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। भाठागांव चौक पर पाइंट ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी भी जांच में सहयोग कर रहे थे।

जांच के दौरान दौरान टाटा एस वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 0865 वहां पहुंचा। निरीक्षक नवल किशोर कश्यप ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रुकने की बजाय पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। यहां तक उसने पुलिसकर्मियों को हटने के लिए कहते हुए धमकी दी कि रास्ते से नहीं हटे तो गाड़ी चढ़ा देगा। इसके बाद वह पुलिसकर्मियों को टक्कर मारते हुए वाहन लेकर आगे बढ़ गया।

वाहन चालक को रोकने के लिए निरीक्षक नवल किशोर कश्यप उसके पीछे दौड़े। इस दौरान चालक ने वाहन को लहराते हुए चलाया और निरीक्षक को टक्कर मार दी। इससे उनके बाएं टखने, बाएं घुटने, बाईं जांघ और पीठ में चोट आई। घटना के बाद चालक गाली-गलौज करते हुए वाहन लेकर फरार हो गया। घायल निरीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार कराया।

चक्रवात अकवान : छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश

■ धान खरीदी केंद्रों पर अलर्ट, आज भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी

रायपुर/गौरेला पेंड्रा मरवाही/धमतरी/खैरागढ़। चक्रवात अकवान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से ही कई जिलों में रुक रुककर बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ गई है।

अकवान साइक्लोन के कारण प्रदेश में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है।

रायपुर मौसम केंद्र ने बताया पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 21 नवंबर को चक्रवाती गतिविधि बढ़ने की संभावना है और यह एक या दो स्थानों को प्रभावित भी कर सकता है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। काले बादल छाए हुए हैं। ठंड बढ़ गई है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर जाने वालों को ठंड बढ़ने से परेशानी का सामाना करना पड़ा।

मौसम में आए इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई और मिसाई का काम चल रहा है। कई किसानों ने धान की कटाई के बाद फसल को खेतों में ही खुले में रखा हुआ है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से कटी हुई धान की फसल भीगने और खराब होने की आशंका बढ़ गई है। धान में नमी आने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की चिंता बढ़ा दी है।

इधर धमतरी में चक्रवात अकवान का असर देखने को मिल रहा है। देर रात से जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। मौसम का मिजाज बदलने और असामयिक बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने गुरुवार देर



शाम जिले के सभी एसडीएम, धान खरीदी केंद्रों के लिए नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों, जिला खाद्य अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को असामयिक वर्षा की आशंका को देखते हुए धान के सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि बेमौसम बारिश के कारण खरीदी केंद्रों में रखा धान खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए धान के स्टैक तैयार कर उन्हें केप कव्हर और तिरपाल से पूरी तरह ढकने की व्यवस्था की जाए। सभी केंद्रों में पर्याप्त संख्या में केप कव्हर उपलब्ध रखने के साथ बारिश से बचाव के इंतजाम पहले से पुख्ता किए जाएं।

कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धान के ढेरों के आसपास पानी जमा होने से रोकने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था अनिवार्य रूप से तैयार करने और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को धान खरीदी केंद्र प्रभारियों और नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिन केंद्रों में धान का उठाव पहले किया जा सकता है, उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता से उठाव कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि खुले में भंडारित धान को मौसम की मार से बचाया जा सके।

धमतरी में देर रात से हो रही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है। धान कटाई और खरीदी के सीजन के बीच अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में खरीदी केंद्रों में भंडारित धान की सुरक्षा और समय पर उठाव प्रशासन के लिए अहम चुनौती बन गई है।

इधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में भी अकवान चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिले के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 20 एवं 21 नवंबर को भारी वर्षा की संभावना जताए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। खुले में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए अपर कलेक्टर ने जिले के सभी 72 धान उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों को एहतियाती इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं।

खरीदी केंद्रों के चबूतरों और फड़ पर रखे धान के बोरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल, पन्नी और कैप कवर उपलब्ध रखने को कहा गया है। इसके अलावा धान के बोरों को जमीन की नमी और बारिश के बहते पानी से बचाने के लिए पर्याप्त डनेज (जमीन से ऊंचा आधार) लगाने तथा फड़ के आसपास की नालियों की सफाई कर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर कलेक्टर ने 22 नवंबर तक केंद्र प्रभारियों और समिति कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मुख्यालय अथवा उपार्जन केंद्र में उपस्थित रहकर भंडारित धान की लगातार निगरानी करने को कहा है। लापरवाही से धान भीगने या क्षति होने पर संबंधित समिति प्रबंधक और उपार्जन केंद्र प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रभारी खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा ने बताया कि जिले के सभी 72 धान खरीदी केंद्रों को तिरपाल से धान ढकने और बारिश का पानी जमा न हो, इसके लिए नालियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है।

यूपी के लिए भाजपा ने तैयार किया आक्रामक मेगा प्लान

मृत्युंजय दीक्षित

मथुरा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अहम मंथन बैठक करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के संकल्प तथा यूजीसी, मतदाता सूची की कमियों और टिकट वितरण पर गहन चर्चा के बाद पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठन व कार्यकर्ता सर्वोपरि के मंत्र के साथ पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपने को अंगद के पांव की तरह जमाने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र परखम में आयोजित मंथन बैठक में संकल्प लिया गया है कि तीसरी तीसरी बार सत्ता मिलते ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर रहेगा। मथुरा की मंथन बैठक में यह भी तय किया गया है कि सर्वाधिक फोकस कार्यकर्ताओं पर ही रहेगा। अब भाजपा में कार्यकर्ताओं को केवल देवतुल्य कहा ही नहीं जाएगा अपितु इसका एहसास भी कराया जाएगा। मंथन बैठक में तय किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला, गरीब, किसान एवं युवा को सशक्त बनाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के कार्यों को आम जनता के मध्य प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। भाजपा अब समाज में प्रबुद्ध, पिछड़ा, दलित एवं युवा सम्मेलन करने के साथ ही सभी मिशन शक्ति केंद्रो पर भी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। भाजपा नये युवा मतदाता व जेन -जी पर भी विशेष ध्यान देगी। देश में जेन -जी आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने के लिए चिंतन किया गया इनकी नाराजगी दूर करने के लिए विशेष अभियान में तीव्रता लाई जाएगी। भाजपा अपने चुनावी अभियान में रक्षात्मक नहीं अपितु आक्रामक प्रचार की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। यूजीसी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच पार्टी के संभावित नुकसान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि सरकार सभी वर्गों के सम्मान, सुरक्षा व हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। चिंतन शिविर में पार्टी व सरकार की अब तक की सभी नीतियों की व्यापक चर्चा की गई। चिंतन शिविर से सबसे बड़ी चर्चा यह रही है कि किन कमियों और अति आत्मविश्वास के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव या कुछ उपचुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। उन सभी कमियों तथा नाराजगी को दूर करते हुए भाजपा संगठन ने 60 प्रतिशत हमारा है और 40 प्रतिशत में बंटवारा है तथा उसमें भी हमारी हिस्सेदारी के संकल्प से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आगामी माह से भाजपा जनआशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। इनका समापन राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ होगा। भाजपा सरकार ने हिंदुत्व तथा सनातन की धार को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 की अवकाश सूची में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती का अवकाश बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में कमी का एक बड़ा कारण जातियों की नाराजगी भी थी उस समस्या को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर सभी जातियों के मध्य पार्टी के सम्मेलन होंगे। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, वैश्य, कायस्थ, भुमिहारऔर राजपूत समाज को पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

जब राज्यों की सफलता बने राष्ट्र की शक्ति

दिनेश कुमार

विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कालजयी कृति गीतांजलि में एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की है, जहां व्यक्ति भयमुक्त होकर सोच सके, ज्ञान की धारा निर्बाध बहे, समाज संकीर्णताओं से ऊपर उठे और सत्य एवं विवेक के मार्ग पर चलते हुए निरंतर प्रगति करे। टैगोर की यह कल्पना केवल किसी आदर्श समाज का स्वप्न नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की आधारभूमि है, जहां स्वतंत्र चिंतन, ज्ञान और मानवीय गरिमा विकास के केंद्र में हों। उनका यह दर्शन आज के राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बेहद प्रासंगिक है।

आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब टैगोर का यह चिंतन नए अर्थों में प्रासंगिक दिखाई देता है। विकास की यात्रा केवल केंद्र की नीतियों से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव को अपनी सामर्थ्य पहचानकर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय विकास की राह में राजनीतिक, क्षेत्रीय और प्रशासनिक संकीर्णताएं जितनी कम होंगी, विकास की गति उतनी ही व्यापक होगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आज से ढाई वर्ष पूर्व 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग कार्उंसिल की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने पर विचार किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत का सपना विकसित राज्यों के माध्यम से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर तक, अर्थात प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए तथा प्रत्येक राज्य और जिले को वर्ष 2047 के लिए अपना विजन तैयार करना चाहिए। यह विचार भारतीय संघीय व्यवस्था में विकास की एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। इसका मूल भाव यह है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा टकराव की नहीं, बल्कि बेहतर परिणाम देने की हो।

नीति आयोग की इस बैठक में कृषि, शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, पेयजल, शासन, डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा जैसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई। राज्यों ने अपने-अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा कीं तथा वर्ष 2047 के लिए राज्य स्तरीय विजन तैयार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों



से भी अवगत कराया।

नीति आयोग ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्यों के प्रदर्शन को विभिन्न सूचकांकों और आकलनों के माध्यम से मापने की व्यवस्था विकसित की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक, नवाचार संबंधी आकलन तथा अन्य प्रदर्शन-आधारित सूचकांक राज्यों को अपनी कमियों को पहचानने और बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने का अवसर देते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्वयं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना करता है और सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है।

इसी क्रम में 27 से 29 दिसंबर 2023 तक आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में 'जीवन की सुगमता' को केंद्र में रखते हुए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा तथा भूमि एवं संपत्ति जैसे पांच प्रमुख विषयों पर विचार किया गया। साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका तथा शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर भी विशेष सत्र हुए।

इन विषयों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विकास की असली परीक्षा किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, बल्कि नागरिक के रोजमर्रा के जीवन में होती है। उसे स्वच्छ पानी कितनी आसानी से मिलता है, बिजली कितनी उपलब्ध है, स्वास्थ्य सेवा कितनी सुलभ है, बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है और उसकी संपत्ति से जुड़ी सेवाएं कितनी सरल तथा पारदर्शी हैं - यही विकास की वास्तविक कसौटियां हैं।

इसी व्यापक सोच के क्रम में नीति आयोग ने अप्रैल 2026 में 'विकसित भारत के लिए डीपीआई@2047' नामक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को आगे बढ़ाने की रणनीति प्रस्तुत की गई है।

भारत की आर्थिक शक्ति का वास्तविक आधार उसके राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं हैं। राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जितना मजबूत होगा, रोजगार, उद्यमिता, सार्वजनिक सेवाओं और नागरिकों की आय के अवसर उतने ही व्यापक होंगे। इसी व्यापक विकास-दृष्टि के अनुरूप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अपने-अपने भविष्य का खाका तैयार करना शुरू किया है।

20 अगस्त 2026 को आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' (एमपीडी-2047) जारी किया। इस मास्टर प्लान में दिल्ली की बढ़ती आबादी और भविष्य की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 लाख नए किफायती आवासों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लैंड पूलिंग, पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से दिल्ली को अधिक समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार राजधानी के रूप में विकसित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

गुजरात ने बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर जोर देते हुए अपनी आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में प्रयास किए हैं। गिफ्ट सिटी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका विकसित करने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

महाराष्ट्र ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक तथा स्थानीय उत्पादन क्षमता को विस्तार देने की दिशा में काम किया है।

तमिलनाडु का ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र, कर्नाटक और तेलंगाना का सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का परिवेश तथा केरल की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपलब्धियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि विकास का कोई एक ही मॉडल नहीं होता। अलग-अलग राज्यों की अपनी परिस्थितियां, क्षमताएं और प्राथमिकताएं होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी विशिष्टताओं को पहचानकर उन्हें विकास की शक्ति में बदलें और जहां दूसरे राज्यों ने अच्छा किया है, वहां से सीखने में संकोच न करें।

इसी दृष्टि से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे उत्तर भारत के राज्यों के सामने भी विकास की एक बड़ी संभावना है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट शक्ति है। पंजाब की कृषि क्षमता, हरियाणा की औद्योगिक शक्ति, खेल और विनिर्माण क्षेत्र में उसकी पहचान, दिल्ली की विशाल सेवा अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक एवं जलविद्युत क्षमता तथा जम्मू-कश्मीर की सामरिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताएं यदि परस्पर पूरक दृष्टि से विकसित की जाएं, तो उत्तर भारत में एक सशक्त आर्थिक क्षेत्र का निर्माण संभव है।

आधुनिक राष्ट्रों की शक्ति केवल उनकी वैचारिक बहसों में नहीं मापी जाती। उसकी असली कसौटी यह है कि वह अपने अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक के जीवन को कितना सुरक्षित, समृद्ध और गरिमापूर्ण बना पाता है। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन शासन की कसौटी अंतत: यही होनी चाहिए कि उससे सामान्य नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया।

रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस 'मुक्त ज्ञान' और 'भय-रहित चित्त' की कल्पना की थी, उसकी पूर्णता आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। जिस नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त होते हैं, वही वास्तव में विकास का लाभार्थी बनता है। इसलिए नीतिगत निर्णयों की कसौटी केवल यह नहीं होनी चाहिए कि उनसे तत्काल राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, बल्कि यह भी होनी चाहिए कि उनसे सामान्य जन के जीवन में कितना स्थायी सुधार आएगा।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है, जब देश का प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ आगे बढ़े और दूसरे राज्यों की उपलब्धियों से सीखने की स्वस्थ परंपरा विकसित करे। विकसित भारत की यात्रा केवल दिल्ली से तय नहीं होगी। यह यात्रा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और देश के प्रत्येक राज्य के गांव, शहर और नागरिक के जीवन से होकर गुजरेगी।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

दृश्यमान बाह्य जगत् (phenomenal world) यथार्थ बाह्य तत्त्व (thing-in-itself) से प्राप्त संवेदनों, और उन संवेदनों को हमारी विचारशक्ति द्वारा दिये गये आकारों से बना हुआ है। संवेदनों के बिना विचारशक्ति वस्तुतत्त्वहीन (contentless) है और ज्ञान के दिये हुये आकारों के बिना संवेदन आकारहीन (blind) हैं।

प्रमाण-प्रमेय-द्वविध्य: दिङ्नाग ने कहा कि वस्तु (reality)दो प्रकार की है। एक बाह्य जगत् में अस्तित्व रखने वाला क्षणिक स्वलक्षण जो कि वैभाषिक के माने धर्मों के समान अनन्त है। वह सर्वथा विशेष तत्त्व है अर्थात् दो या अधिक स्वलक्षणों में कोई सामान्य तत्त्व द्रव्य या अवयवी या जाति के रूप में नहीं। प्रत्येक अपने में अलग तत्त्व है।

वह स्वलक्षण समय की दृष्टि से क्षणिक है और देश की दृष्टि से रेखागणित के बिन्दु के समान है, जिसमें कोई लम्बाई या चौड़ाई नहीं है।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि पहिले (पृ06 पर) कहा गया है, वह स्वलक्षण समय की दृष्टि से (temporally) स्थिरता (duration) नहीं रखता, और देश की दृष्टि से (spatially) विस्तार (e&tension) नहीं रखता, अर्थात् यथार्थ तत्त्व (reality) समय की दृष्टि से लम्बाई में (vertically) सब ओर से कटी हुई है, और देश की दृष्टि से चौड़ाई में (horizontally) सब ओर से कटी हुई है अर्थात् वह एक बिन्दुमात्र है जिसमें कोई अवयव नहीं, अथवा स्वलक्षणों को यदि अवयव समझें तो उन अवयवों में रहने वाला कोई अवयवी या द्रव्य नहीं। अथवा अनेक क्षणों में रहने वाली वस्तु के समान उन अनेक क्षणों में रहने वाला कोई सामान्य धर्मी तत्त्व नहीं, क्योंकि स्वलक्षण एक ही क्षण रहता है।

क्रमश: ...

सीवी रमन ने भारत को दिलाई विज्ञान की दुनिया में एक अलग पहचान

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 21 नवंबर को देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन का निधन हो गया था। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। लेकिन रमन प्रभाव सबसे ज्यादा अहम है। डॉ सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार उनके जीवन के आधे पड़ाव पर ही मिल गया था। सीवी रमन ने अपना पूरा जीवन देश में विज्ञान और उसकी शिक्षा के लिए लगा दिया। सीवी रमन एक कर्मठ, समर्पित वैज्ञानिक, शिक्षक और देशभक्त के रूप में कार्य करते रहे।

ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में 07 नवंबर 1888 को चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर था और मां का नाम पार्वती अम्मल



था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। रमन पढ़ाई करने में काफी तेज थे। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा दी और पहली पोजिशन पाया। वहीं साल 1903 में 14 साल की उम्र में सीवी रमन को हॉस्टल भेज दिया गया। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उनको बचपन से ही भौतिकी में काफी रुचि थी। साल 1904 में उन्होंने डिग्री हासिल की और फिजिक्स और इंग्लिश में मेडल दिया गया था।

सीवी रमन उन वैज्ञानिकों में नहीं थे, जो सिर्फ अपने प्रयोगों में डूबे रहते थे। साल 1926 में उन्होंने इंडियन जनरल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1933 में बेंगलुरू में भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले निदेशक का पद संभाला। फिर इसी साल उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना भी की। साल 1948 में सीवी रमन के भारतीय विज्ञान संस्थान से सेवानिवृत्त होने के एक साल बाद उन्होंने रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। फिर साल 1970 तक वह इसी संस्थान में सक्रिय रहे।

बता दें कि रमन ने जीवनभर में कई खास खनिज, पत्थर और अन्य पदार्थ जमा किए। उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन गुणों के लिए एकत्र किया था। जिनमें से कुछ उन्होंने खुद तलाश किए थे। तो कुछ उनको उपहार के रूप में मिले थे। सीवी रमन अपने साथ हमेशा एक छोटा स्पैक्ट्रोस्कोप रखा करते थे। इसको आज भी आईआईएससी में देखा जा सकता है।

डॉ. सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उसी दिन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। खगोल वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के भतीजे थे जिन्हें 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं रमन के वैज्ञानिक जीवन में लॉर्ड रदरफोर्ड का बहुत योगदान था। उन्होंने ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था और 1932 में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक पद के लिए उनकी अनुशांसा की थी।

वहीं 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में सीवी रमन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

वीटो पावर से लैस अमेरिका, चीन, रूस की दोस्ती से सब हैरान

नीरज कुमार दुबे

वीटो पावर से लैस अमेरिका, चीन और रूस अब तक वैश्विक राजनीति में अलग-अलग खेमों से अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज चीन के शेनझेन में हुई तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात ने एक नए वैश्विक समीकरण की संभावना पैदा करते हुए मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने की रणनीति बनाई है। बैठक के निष्कर्ष साफ दर्शा रहे हैं कि दुनिया की इन तीन महाशक्तियों के नेताओं ने अब आपसी टकराव के बजाय साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया है। अगर यह नजदीकी ठोस सहयोग में बदलती है तो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य संतुलन पर इन तीनों का सामूहिक प्रभाव और बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि करीब 90 मिनट चली इस ऐतिहासिक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियारों, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा की।

साथ ही बैठक के बाद तीनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसे चीन के सरकारी मीडिया ने पीस डिक्लेरेशन यानी शांति घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया। घोषणा में रणनीतिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और परमाणु जोखिम कम करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। लेकिन इस मुलाकात का वास्तविक महत्व घोषणा के शब्दों से कहीं आगे है। यह उस वैश्विक व्यवस्था में तीन बड़ी शक्तियों के सीधे संवाद का संकेत है, जहां पिछले कुछ वर्षों से टकराव, प्रतिबंध, युद्ध और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हावी रही है।

संयुक्त घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक पहलू रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने का संकल्प है। तीनों देशों ने दुनिया के हित में स्थिर ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने पर जोर दिया है। अमेरिका, रूस और चीन का इस मुद्दे पर एक साथ आना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस ऊर्जा का बड़ा उत्पादक और



निर्यातक है, चीन दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है और अमेरिका वैश्विक ऊर्जा उत्पादन तथा व्यापार में बड़ी भूमिका निभाता है।

अगर इन तीनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग वास्तविक रूप लेता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की दिशा, कीमतों और ऊर्जा कूटनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसका सामरिक अर्थ यह है कि ऊर्जा अब केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और भू-राजनीतिक ताकत का प्रमुख हथियार है।

साथ ही परमाणु हथियारों को लेकर भी तीनों नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे लड़ा जाना चाहिए। तीनों देश परमाणु जोखिम घटाने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करेंगे। देखा जाये तो दुनिया के तीन बड़े परमाणु शक्ति केंद्रों के बीच इस तरह का संवाद रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही घोषणा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रतिबद्धता है। तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और अन्य समान संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का विरोध किया है।

देखा जाये तो यह मुद्दा रूस के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसका रूस लगातार विरोध करता रहा है। अब अमेरिका, रूस और चीन ने संयुक्त रूप से कहा है कि किसी देश के सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का सम्मान किया जाना चाहिए और आईसीसी जैसी संस्थाओं को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि तीनों महाशक्तियां अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव चाहती हैं। वे ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की पैरवी कर रही हैं, जिसमें इन तीनों देशों के हितों और प्रभाव को अधिक महत्व मिले।

इस बैठक का सबसे दिलचस्प पहलू यूक्रेन युद्ध रहा। ट्रंप चाहते थे कि चीन और रूस के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी इस मुद्दे को उठाया। पुतिन ने भी कहा कि तीनों देशों के बीच यूक्रेन सहित क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान को लेकर साझा हित हैं। हालांकि चीन ने बैठक के शुरुआती वक्तव्य में यूक्रेन का सीधा उल्लेख नहीं किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाद में स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध त्रिपक्षीय बैठक का केंद्रीय विषय नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि बीजिंग इस मंच को केवल रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं है। चीन की प्राथमिकता अमेरिका के साथ संबंधों को स्थिर करना और वैश्विक कूटनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका मजबूत करना है।

इसके अलावा, चीन-अमेरिका संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दा ताइवान भी इस घटनाक्रम के केंद्र में रहा। त्रिपक्षीय बैठक से पहले शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिका से ताइवान के मामले में सही कदम उठाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर गलत फैसले चीन-अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसे सैन्य सहायता और हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। ट्रंप पहले ही ताइवान को नई हथियार बिक्री रोकने को बातचीत के एक संभावित विकल्प के रूप में पेश कर चुके हैं। ऐसे में चीन की कोशिश स्पष्ट है कि वह रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और अमेरिका के साथ सीधे संवाद का इस्तेमाल करके ताइवान के मुद्दे पर वाशिंगटन की नीति को प्रभावित करना चाहता है।

इसी बीच जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने स्पष्ट किया कि ताइवान पर जापान की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन-जापान के बीच पहले से जारी तनाव को देखते हुए यह बयान बताता है कि शेनझेन में महाशक्तियों की कूटनीति का असर पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा राजनीति पर पड़ सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस ऐतिहासिक मुलाकात को वैश्विक मीडिया ने अपने-अपने नजरिये से देखा है। अमेरिकी मीडिया में इस सम्मेलन को ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में प्रमुखता मिली है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस बात पर जोर है कि तीनों नेताओं की मुलाकात ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन यूक्रेन, ईरान, व्यापार और परमाणु हथियारों पर उनके मतभेद इतने गहरे हैं कि किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी रिपोर्टिंग में ट्रंप के भव्य स्वागत और राजनीतिक प्रदर्शन को भी खास महत्व दिया गया है।

वहीं रूसी मीडिया, खासकर सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस, ने इस बैठक को तीनों महाशक्तियों के बीच सहयोग की नई संभावना के रूप में पेश किया है। रूसी मीडिया रिपोर्टिंग में पुतिन के इस बयान को प्रमुखता मिली है कि तीनों देशों के क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में साझा हित हैं। क्रेमलिन ने पुतिन और ट्रंप की अलग-अलग मुलाकात को भी सकारात्मक बताया है। रूसी मीडिया के लिए यह मुलाकात पश्चिमी प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव के बीच मॉस्को की वैश्विक स्वीकार्यता प्रदर्शित करने का अवसर भी है।

आज का इतिहास

1877 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया।
1906 चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई।
1921 प्रिंस ऑफ वेल्स (सम्राट एडवर्ड अष्टम) बॉंबे (अब मुंबई) पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया।
1947 आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया।
1956 एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी।
1962 भारत-चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्षविराम का ऐलान किया।
1963 केरल के थुंबा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरु हुआ।
1963 भारत का नाइक-अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया।
1979 मक्का में काबा मस्जिद पर मुस्लिम उग्रवादियों का अधिकार।
1986 मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया।
1999 चीन द्वारा अपने प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान %शेनझू% का प्रक्षेपण किया गया।
2001 संयुक्त राष्ट्र ने अफ़ग़ानिस्तान में अंतरिम प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा।
2002 मुस्लिम लीग (कायदे आजम) के नेता जफ़रउल्ला ख़ान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित।
2002 बुल्गारिया. इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लेवानिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया।
2005 श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्नसिरी विक्रमनायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
2006 भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।
2007 पैप्सिको चैयरमैन इंदिरा नूई को अमेरिकी इंडियन बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल में शामिल किया गया।
2008 प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8त्न रहने की सम्भावना व्यक्त की। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पंजाब और हरियाणा में दो नये जजों जस्टिस राकेश कुमार गर्ग व राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया।
2019 स्वीडन की 17 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित।

पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा बांग्लादेश, विरोधियों के निशाने पर पूर्व हुक्मरान

नीरज कुमार दुबे

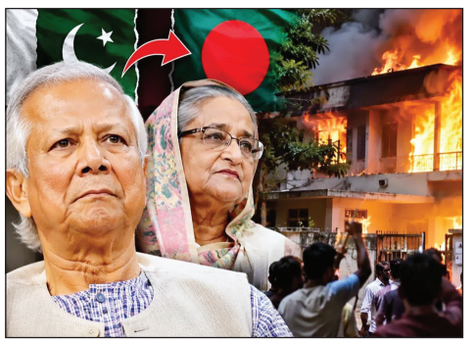
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस राजनीतिक प्रतिशोध और अराजकता की पटकथा लिखी गई थी, अब उसी की आग मुहम्मद यूनुस के घर तक पहुंच गई है। कभी अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में देश की सत्ता संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी मकान में आग लगा दी गई है। देखा जाये तो यह घटना महज एक मकान में आगजनी का मामला नहीं है, बल्कि उस बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति का आईना है, जिसे यूनुस के नेतृत्व में नई दिशा देने का दावा किया गया था।

विडंबना देखिए कि जिस शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद उनके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें हुईं, आज उन्हीं घटनाओं की परछाईं यूनुस के अपने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देखा जाये तो बांग्लादेश की राजनीति अब इस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता बदलने के बाद पूर्व हुक्मरानों को राजनीतिक विरोधी नहीं, बल्कि दुश्मन की तरह देखा जाने लगा है। पाकिस्तान में जिस तरह सत्ता से बाहर हुए नेताओं और उनके परिवारों को राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ता रहा है, बांग्लादेश में भी वैसी ही तस्वीर उभरने लगी है।

हम आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात चटगांव के पंचलैश इलाके में स्थित यूनुस के पुश्तैनी मकान के भूतल पर बने एक खाली कमरे में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे आग लगी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घटना की जांच शुरू कर दी। मकान के ऊपरी हिस्सों में यूनुस के भाइयों के परिवार रहते हैं। इस घटना के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

लेकिन यह हमला किसी अकेली घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। पिछले दस दिनों से बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में बम धमाकों, वाहनों को जलाने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की कम से कम 37 शाखाओं और कार्यालयों को भी आगजनी या आग लगाने की कोशिशों का निशाना बनाया गया है। देश के कम से कम 28 जिलों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि बांग्लादेश में प्रतिशोध की राजनीति अब किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं रह गई है। शेख हसीना के खिलाफ जिस राजनीति को बढ़ावा मिला था अब उसी का सामना यूनुस कर रहे हैं

हम आपको याद दिला दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता कायम करने और देश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने की थी। लेकिन उनके कार्यकाल की पहचान धीरे-धीरे राजनीतिक टकराव, अवामी लीग पर प्रतिबंध और पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई से



जुड़ती चली गई।

अवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगाई गई। पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना को देश से बाहर रहने के दौरान मुकदमे का सामना करना पड़ा और नवंबर 2025 में विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। इस पूरी प्रक्रिया ने बांग्लादेश की राजनीति में गहरी खाई पैदा कर दी।

यूनुस के शासनकाल में शेख मुजीबुर्रहमान के ऐतिहासिक आवास और 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े प्रतीकों पर भी हमले हुए। जिन प्रतीकों को बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना जाता था, वे भी राजनीतिक उन्माद की भेंट चढ़े। ऐसे माहौल में लोकतंत्र की मजबूती के बजाय राजनीतिक बदले की भावना को बढ़ावा मिलने का आरोप लगातार गहराता गया।

यूनुस के कार्यकाल की एक बड़ी विफलता भारत के साथ बांग्लादेश के पारंपरिक रिश्तों में आई गिरावट रही। शेख हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ था। लेकिन हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए। यूनुस सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी और दोनों देशों के बीच अविश्वास ने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। भारत के साथ रिश्तों में आई इस तल्खी ने बांग्लादेश की क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति को भी कमजोर किया।

दूसरी तरफ, कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक समूहों के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ीं। कई हिंदुओं को बुरी तरह जान से मारा भी गया। इन परिस्थितियों ने बांग्लादेश की उस धर्मनिरपेक्ष पहचान को चुनौती दी, जिसकी नींव 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद रखी गई थी। भारत के साथ तनाव और कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव की आशंकाओं ने देश के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

आज बांग्लादेश में हालात यह हैं कि शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है। हसीना दिसंबर में स्वदेश लौटने की बात कह चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके नए पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों की मांग स्वीकार नहीं की है। इसी राजनीतिक टकराव के बीच हिंसा भड़क रही है। पुलिस ने राजधानी ढाका में 24 घंटे के अभियान में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के नाम पर नई व्यवस्था और लोकतांत्रिक भविष्य का वादा किया गया था, वह आखिर कहां पहुंच गया? जिस नेता की सरकार ने पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी, उसी नेता के परिवार के पुश्तैनी मकान तक आग पहुंच गई। ग्रामीण बैंक जैसी संस्था भी हिंसा का निशाना बन रही है।

देखा जाये तो मुहम्मद यूनुस के सामने अब वही चुनौती खड़ी है, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में शेख हसीना के सामने खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि हसीना फिलहाल सत्ता में नहीं हैं, जबकि यूनुस भी अब पूर्व अंतरिम शासन प्रमुख बन चुके हैं। बांग्लादेश की राजनीति में बदले की जिस आग को बुझाने की जरूरत थी, वह अब और फैलती दिखाई दे रही है।

बहरहाल, बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक भविष्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संकट है। पाकिस्तान की तरह अगर वहां भी हर सत्ता परिवर्तन के साथ पुराने हुक्मरानों को मिटाने और उनके समर्थकों को कुचलने की परंपरा मजबूत होती गई, तो लोकतंत्र महज सत्ता हासिल करने और विरोधियों को खत्म करने का औजार बनकर रह जाएगा।

प्रतिबद्धताएं पूरी हों तभी विकसित भारत का निर्माण होगा

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

एक ऐसी जिला अधिकारी की कल्पना करें, जो हर महीने पूरक पोषण कार्यक्रम की समीक्षा करती हैं। यह समीक्षा आमतौर पर किसी कॉन्फ्रेंस रूम में होती है, जहां स्क्रीन पर आंकड़े दिखाए जाते हैं। अब कल्पना करें कि वही अधिकारी प्रत्येक समीक्षा से पहले सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन ब्लॉकों में से प्रत्येक के एक आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करने का फैसला करती हैं। वहां वे माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से बातचीत करती हैं। इस तरह उन्हें किसी पोषण सामग्री का स्टॉक खत्म होने की जानकारी किसी भी रिपोर्ट में दर्ज होने से पहले ही मिल जाती है। न तो किसी नियम में बदलाव हुआ है और न ही किसी नई योजना की घोषणा की गई है। फिर भी, अंतिम स्तर पर रहने वाले नागरिक को अब सरकार का एक अलग रूप देखने को मिला है। यही कर्मयोगी संकल्प की मूल भावना है। यह वह दृढ़ संकल्प है, जिसकी शुरूआत कैबिनेट सचिव ने 17 नवंबर को भारत मंडपम में की। नीति आयोग द्वारा 'मिशन के रूप में नेतृत्व' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का यह समापन समारोह था। यह संकल्प केवल एक वाक्य का है—'मैं जिन नागरिकों की सेवा करता/करती हूं, उनके भले के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी नेतृत्व की विधि में एक बदलाव लाने का संकल्प लेता/लेती हूं।' प्रत्येक अधिकारी उस स्थिति की पहचान करता है, जिसमें वह यह कदम उठाएगा। इसके बाद वह विकसित किए जाने वाले नेतृत्व के गुण का चयन करता है, निर्धारित तिथि के साथ कार्रवाई का विवरण देता है और नागरिकों के लिए अपेक्षित परिणाम का वर्णन करता है। इस प्रतिबद्धता को आईगॉट (द्बत्रह्ल्ल) प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है।

कार्यशाला में उन्हें यह अंतर समझने के लिए कहा गया कि किन बदलावों के लिए दूसरों के अधिकार या मंजूरी की आवश्यकता होती है और कौन से बदलाव ऐसे हैं, जिन्हें वे अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। अधिकांश अधिकारियों ने पाया कि दूसरी श्रेणी में आने वाले कार्यों की सूची उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार, नेतृत्व कोई पद नहीं, बल्कि एक कार्य-प्रणाली है। इसका उपयोग किसी मंत्रालय के सचिव से लेकर किसी आकांक्षी ब्लॉक में तैनात एक युवा क्षेत्रीय अधिकारी तक, कोई भी कर सकता है। 'मिशन के रूप में नेतृत्व' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की शृंखला में पहली कार्यशाला थी। वहां 'नागरिक देवो भव' के मार्गदर्शक विचार को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि नागरिक को देवता के समान मानकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों के अनुभवों से कार्यशाला में नेतृत्व के जिन गुणों की पहचान की गई, उनमें ध्यान से सुनना, समानता, सहानुभूति, ईमानदारी और कठिन निर्णय लेने में निडरता शामिल है। क्षमता का अंतिम मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पूरे किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसके काम करने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव आया है, जिसे नागरिक स्वयं महसूस कर सके। ऐसी प्रतिबद्धता, जिसमें एक तय तिथि, अपेक्षा के अनुसार परिणाम और प्रगति की समीक्षा या अगली कार्रवाई शामिल हो, का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह अधिकारी को एक पेशेवर के रूप में सम्मान देती है, जो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की पहचान स्वयं कर सकता है। कार्यशाला की रूपरेखा ने भी इसी विश्वास को दर्शाया है। इसमें अधिकारियों ने छात्रों, विद्वानों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सामुदायिक भागीदारों के साथ एक ही मेज पर बैठकर विचार-विमर्श किया। नागरिकों ने उन लोगों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो प्रशासनिक निर्णयों के परिणामों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।

भारत की राजनीति में आरोप नही प्रमाण की जरूरत

कांतिलाल मांडोत

भारतीय लोकतंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल उठाने और आरोप लगाने के बीच एक बड़ा अंतर होता है। किसी भी राजनीतिक दल को जनता के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, मगर उस बात के समर्थन में ठोस प्रमाण भी होने चाहिए। केवल भाषणों, नारों और आरोपों से न तो लोकतंत्र मजबूत होता है और न ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी राजनीति को आरोपों से निकालकर तथ्यों और जनहित के मुद्दों तक लेकर आएं।

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट ने एक बार फिर देश की राजनीति में बहस छेड़ दी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और वर्ष 2014 के बाद की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा लगाया गया और विपक्ष उस समय सदमे में था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को कांग्रेस के दो प्रमुख हथियार बताते हुए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की लड़ाई लड़ने की बात कही।

लोकतंत्र में राहुल गांधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई नेता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना गंभीर आरोप लगाता है तो उससे अपेक्षा होती है कि वह जनता के सामने ठोस प्रमाण भी रखे। केवल यह कह देना



कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, पर्याप्त नहीं है। यदि चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है तो उसका विवरण, तथ्य और प्रमाण सामने आने चाहिए। जनता को भी यह समझना जरूरी है कि आरोप राजनीतिक भाषण का हिस्सा हैं या वास्तव में किसी गंभीर अनियमितता का प्रमाण।

भारत समिट में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर भी भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों जगह दे रही है, जिनके संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसायटी नेटवर्क और एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने इक्वाडोर के पूर्व मंत्री गुइलेर्मो लांग और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी का उल्लेख करते हुए उनकी पृष्ठभूमि और भारत से जुड़े पुराने बयानों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इन लोगों को मंच देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है।

भाजपा नेता सीआर केसवन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रायोजित भारत समिट में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने देश तथा लोकतंत्र के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल कुछ विदेशी प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिलिबेक ने अपने भाषण में कांग्रेस का नारा वोट चोर गद्दी छोड़ लगाया था। वीडियो में राहुल गांधी तालियां बजाते दिखाई दिए। इस पर रिजिजू ने सवाल किया कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अपमान करता है तो उस समय कौन हंसता है?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश के आंतरिक राजनीतिक मुद्दे उठाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मृत व्यक्तियों, दोहरे मतदाताओं और स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाना आवश्यक है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया को ही गलत बताना उचित नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत को बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के बजाय गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ना चाहिए। शाह ने कांग्रेस की लगातार चुनावी हार का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी अपना राजनीतिक असंतोष अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। उन्होंने कृषि, उद्योग, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई शिक्षा नीति जैसे क्षेत्रों में पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और उन पर भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ है।

कांग्रेस के लिए इन राजनीतिक सवालों में एक बड़ी सीख छिपी है। जनता केवल भाषण सुनकर अपना निर्णय नहीं करती। वह सरकार के काम, नेताओं के व्यवहार और उनके दावों की सच्चाई भी देखती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने लगे तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। बार-बार बड़े आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। झूठ और अधूरे तथ्यों का पुलिंदा लंबे समय तक नहीं चल सकता। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है।

आज का युवा, विशेषकर नई पीढ़ी, रोजगार, शिक्षा, तकनीक, अवसर और देश के भविष्य को लेकर गंभीर है। वह केवल राजनीतिक नारे नहीं सुनना चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में सुधार के लिए कौन क्या कर रहा है। यदि राजनीति का केंद्र केवल विरोध और आरोप बन जाएगा तो युवा उससे दूरी बना सकता है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सरकार का विरोध करते-करते देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा से बचना भी उतना ही जरूरी है। देश की कमियों पर सवाल उठाना देशविरोध नहीं है, लेकिन आलोचना तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।

कांग्रेस का जनाधार कमजोर होने के पीछे भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। पार्टी को यह देखना होगा कि जनता उससे क्यों दूर हो रही है। केवल भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को निशाना बनाने से राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकता। देश की जनता को विकास, सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक सद्भाव और मजबूत नेतृत्व चाहिए।

यूपी: 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब होने के दावे पर राजनीतिक घमासान

अजय बोकिल

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे कि राज्य में एसआईएस के चलते 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब हैं, पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने यह कहकर पानी फेर दिया कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोटरों का हिसाब नहीं रखता। मीडिया से चर्चा के दौरान रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटों के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा नहीं है। आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण भी नहीं करता। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि योगी ने लगभग सवा करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का दावा किस आधार पर किया? क्या उनके पास इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े हैं या फिर वो विस चुनाव के मद्देनजर साम्प्रदायिक आधार पर कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? वैसे भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल पूछा था कि योगी के दावे की बुनियाद क्या है?

बताया जाता है कि योगी के दावे का आधार पंचायत, नगरीय निकाय और निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों का अंतर है। हालांकि योगी के दावा अगर सही है तो फिर राज्य में एसएसआर और मतदाता सूची अप टेशन पर सवाल खड़े होते हैं कि वोटर लिस्ट का अद्यतनीकरण किस आधार और प्रक्रिया के साथ किया गया? इस बीच योगी के इस 'खुलासे' के बाद भाजपा ने यूपी में अपने कार्यकर्ताओं को गायब अथवा कटे नाम मतदाता सूची में जोड़ने के काम में लगा दिया है। हर बूथ पर कम से कम 50 और हर विधानसभा क्षेत्र में 25 हजार नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। जाहिर है कि जोड़े



जाने वाले ये वोट मुख्यत: हिन्दुओं के ही हैं। भाजपा का यह 'वोट जोड़ो अभियान' 16 दिसंबर तक चलेगा।

इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक टीवी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान किए गए दावे से हुई। इसमें योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.65 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं क़रीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। योगी ने स्पष्ट किया कि वे उन 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं की बात कर रहे हैं, जिनके नाम यूपी की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये नाम कैसे ग़ायब हो गए? इसके पीछे कौन था? यही नहीं, योगी ने यह भी कहा कि ऐसे 66 लाख मतदाता हैं। इनमें 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं। साथ ही 18-19 साल की उम्र के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। योगी के इस कथन के बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया। बीते मंगलवार को लखनऊ में जब राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ,अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस देखें तो उसमें मतदाता का नाम, रिश्ते की जानकारी जैसे पिता, पति या पत्नी का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां ही होती हैं। इस डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी कोई दूसरी जानकारी नहीं है। इसलिए मतदाता सूची के आधार पर इन पहलुओं पर विश्लेषण करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। इसे डाउनलोड सॉफ्टवेयर की मदद से नामों के आधार पर लोगों के धर्म या लिंग का अनुमान लगाकर विश्लेषण किया जा सकता है। रिणवा ने स्पष्ट किया कि सीएम के बयान में हिंदू वोटरों के 'गायब' होने की बात कही गई है न कि नाम काटने की। हमारा अंदाज है कि ऐसे 2.58 करोड़ मतदाता गायब हैं। लेकिन कोई नाम टारगेटेड तरीके से नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कुछ 18 लाख 84 हजार वोट बढ़े ही हैं।

ऐसे में यह सवाल फिर मौजूं हो गया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट गायब होने का आंकड़ा आया कहां से? नाम गायब होने के मुद्दे पर सही कौन है, योगी आदित्यनाथ अथवा सीईओ रिणवा? दूसरे, यह मुद्दा उछाल कर योगी कौन सा राजनीतिक दांव साध रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक तरफ जहां राज्य में हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मुसलमानों के वोटो में 1.65 फीसदी की वृद्धि को लेकर भी चेताया। इसमें संदेश साफ था कि अगर राज्य में मुस्लिम वोट बढ़े और हिंदू वोट घटे तो फिर से कथित रूप से हिंदू विरोधी पार्टियां सत्ता में आ जाएंगी।

हो सकता है कि ऐसे में राज्य में नाराज बैठा अथवा आपस में उलझा भाजपा कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो जाए और हिंदू वोटर नए सिरे से भाजपा के पक्ष में लामबंद हो जाएं। हालांकि ऐसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूंकि यूपी में अगले विस चुनाव में भाजपा नीत एनडीए और सपा-कांग्रेस संभावित गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होना है, इसलिए योगी अभी से हिंदू वोटों को लामबंद करने में जुट गए हैं। 1.27 करोड़ वोटों का आंकड़ा इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2022 के विस चुनाव में भाजपा और मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को मिले कुल वोटों में केवल 85 लाख 7 हजार वोटों का ही अंतर था। अगर सपा के साथ बसपा को मिले वोट भी जुड़ जाते तो भाजपा तभी सत्ता से बाहर हो गई होती।

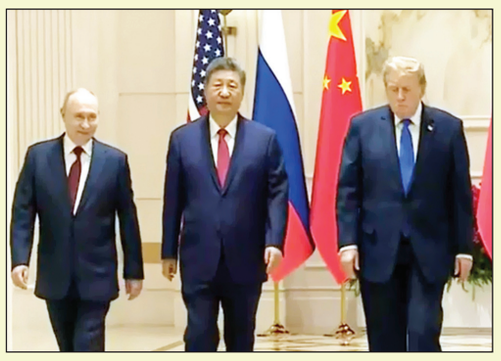
भाजपा के लिए राहत की बात यही है कि सपा-बसपा पहले भी अलग-अलग लड़े थे और इस बार भी अलग ही लड़ने वाले हैं। अलबत्ता चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों ने मिलकर 'भीम और मीम' गठबंधन बनाया है, जो किसे और कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। माना यही जा रहा है कि यह गठबंधन चुनाव में सपा-बसपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कुछ जगह भाजपा का भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहां प्रश्न यह भी है कि योगी के दावे की चुनाव आयोग ने हवा क्यों निकाली? क्या यह किसी 'ऊपरी' इशारे पर हुआ अथवा सीईओ रिणवा केवल तथ्यात्मक बात कह रहे थे?

यह प्रश्न राजनीतिक हलकों में इसलिए भी तैर रहा है कि विस चुनाव को लेकर सीएम योगी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच अघोषित टसल अभी थमी नहीं है। ऐसे में योगी को पार्टी पूरा 'फ्री हैंड' देगी, ऐसा नहीं लगता। ताजा बवाल उस कथित 209 भाजपा प्रत्याशियों की नामों की सूची को लेकर भी है, जिसके बारे में चर्चा थी कि योगी ने अपनी पसंद के नाम हाईकमान को भेज दिए हैं।

तीन महाशक्तियां, एक मंच और बदलती दुनिया

देवेश त्रिपाठी

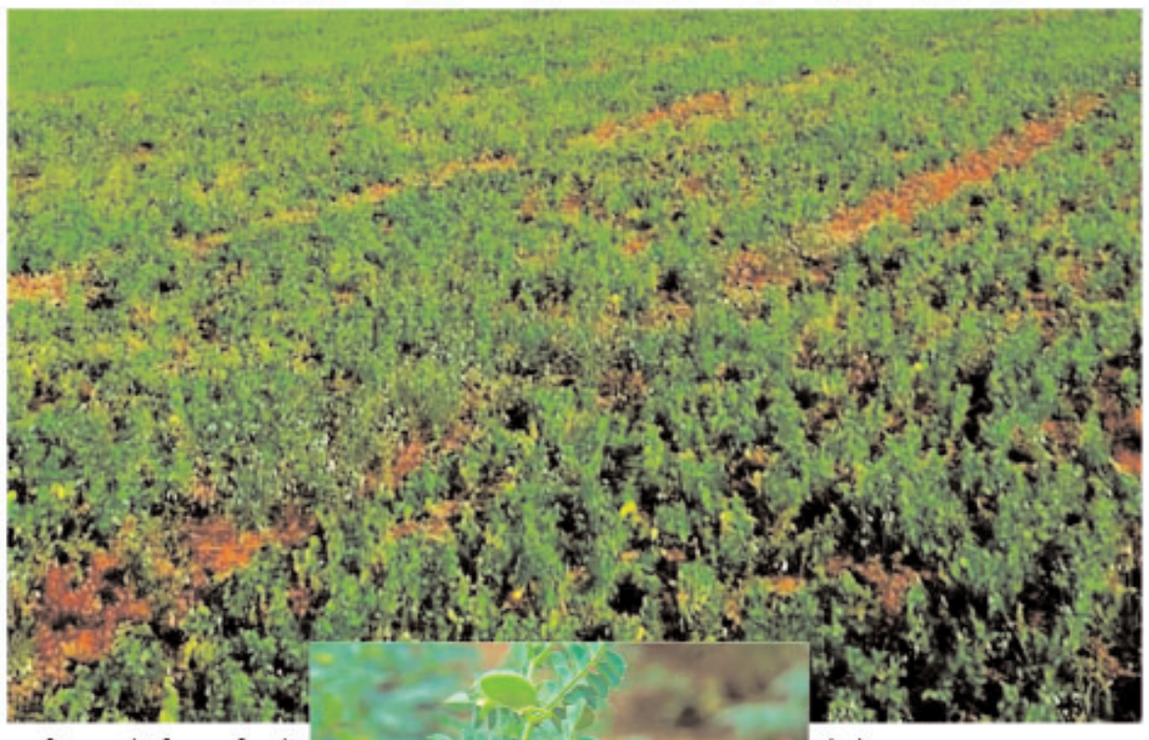
चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की करीब 90 मिनट तक चली बहुचर्चित मुलाकात भले ही प्रमुख विवादों और परमाणु हथियारों से जुड़े किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंची, लेकिन अगर दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के शीर्ष नेता एकसाथ बैठकर वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हों, तो यह अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना बन जाती है। ट्रंप ने इस बातचीत को परमाणु हथियारों के जखीरे में कटौती और उनसे जुड़े जोखिमों को कम करने की जरूरत से जोड़ा। दूसरी ओर, जिनपिंग ने परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और उनके उन्मूलन की वकालत की। हालांकि, चीन अब तक त्रिपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा बनने से बचता रहा है। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन, दोनों इसका अंत चाहते हैं, वहीं पुतिन ने क्षेत्रीय विवादों के समाधान में साझा हितों की बात कही। तीनों नेताओं का यह जमावड़ा वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत अवश्य देता है। पहले जहां वैश्विक संस्थाओं और बहुपक्षीय विचार-विमर्श पर बल दिया जाता था, वहीं अब बड़ी ताकतों के बीच 'व्यक्तिगत' स्तर पर मामलों को संभालने का चलन बढ़ता दिख रहा है, जबकि यूरोप और अन्य छोटे व मध्यम दर्जे की ताकतें धीरे-धीरे हाशिये पर जा रही हैं। हालांकि, बड़े देशों के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण से मझोली शक्तियों के लिए एकजुट होकर काम करने का



यह एक अवसर भी हो सकता है। इस मुलाकात से पुतिन को जरूर कूटनीतिक लाभ मिला है। अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर उनकी मौजूदगी ने रूस को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिशों के बीच मॉस्को को अपनी अहमियत प्रदर्शित करने का मौका दिया। वहीं, बैठक की मेजबानी करने वाले शी जिनपिंग के लिए यह वाशिंगटन के साथ बराबरी के स्तर पर संवाद करने और चीन के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को रेखांकित करने का अवसर भी था। बिना किसी स्पष्ट और पूर्व निर्धारित एजेंडे के हुई इस बैठक से किसी बड़ी नीतिगत सफलता की उम्मीद करना बेमानी था। फिर भी, इसका प्रतीकात्मक महत्व नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली चिंता यह है कि अगर वैश्विक व्यवस्था कुछ देशों के आपसी समीकरणों और हितों तक सिमटती है, तो इससे छोटे व मध्यम देशों की संप्रभुता तथा सामूहिक हित प्रभावित हो सकते हैं। तीन बड़ी शक्तियों की यह मुलाकात इसलिए केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि उभरती नई विश्व व्यवस्था का संकेत भी है।

किसान चने की इन 3 किस्मों की करें खेती,

कम लागत और समय में मिलेगी बंपर पैदावार



किसान चने की इन 3 किस्मों की करें खेती, कम लागत और समय में मिलेगी बंपर पैदावार; जानिए खासियत और लाभ - रबी फसलों की बुवाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में किसान मुख्य तौर पर चना, गेहूं और सोयाबीन की फसल बोते हैं। ऐसे में अन्नदाताओं को अच्छी किस्म के बीजों की आवश्यकता होती है ताकि वह अच्छी पैदावार ले सके। हालांकि, बाजार में रबी फसलों की बहुत सी अधिक उत्पादन देने वाली किस्में है मौजूद है लेकिन इनकी जानकारी हर किसान को नहीं होती है। ऐसे में यहां हम आपको चने की अधिक उत्पादन देने वाली टॉप 3 किस्मों की जानकारी देंगे, ताकि आप कम लागत और समय में बढ़िया मुनाफा कमा सकें। आइए जानें किस्नों की खासियत और लाभ किसान क्रेडिट कार्ड

1. विदिशा (वीजी 1084) डब्ल्यूबीजी 29 — पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए वरदान
   - रिलीज वर्ष: 2015 (एसवीआरसी)
   - उद्गम केंद्र: बेरहामपुर, पश्चिम बंगाल
   - औसत उपज: लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
   - परिपक्वता अवधि: 131 दिन
   - उपयुक्त क्षेत्र: पश्चिम बंगाल
   - विशेष लक्षण: पछेती बुवाई की स्थिति में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन
   - मुख्य विशेषता: छोटे बीजों वाली मध्यम परिपक्व देसी किस्म (12-14 ग्राम प्रति 100 बीज)

यह किस्म देरी से बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है और उपज के मामले में अन्य देसी किस्मों से काफी बेहतर मानी जाती है।

2. बीडीएनजीके 798 — महाराष्ट्र के किसानों के लिए उपयुक्त काबुली किस्म

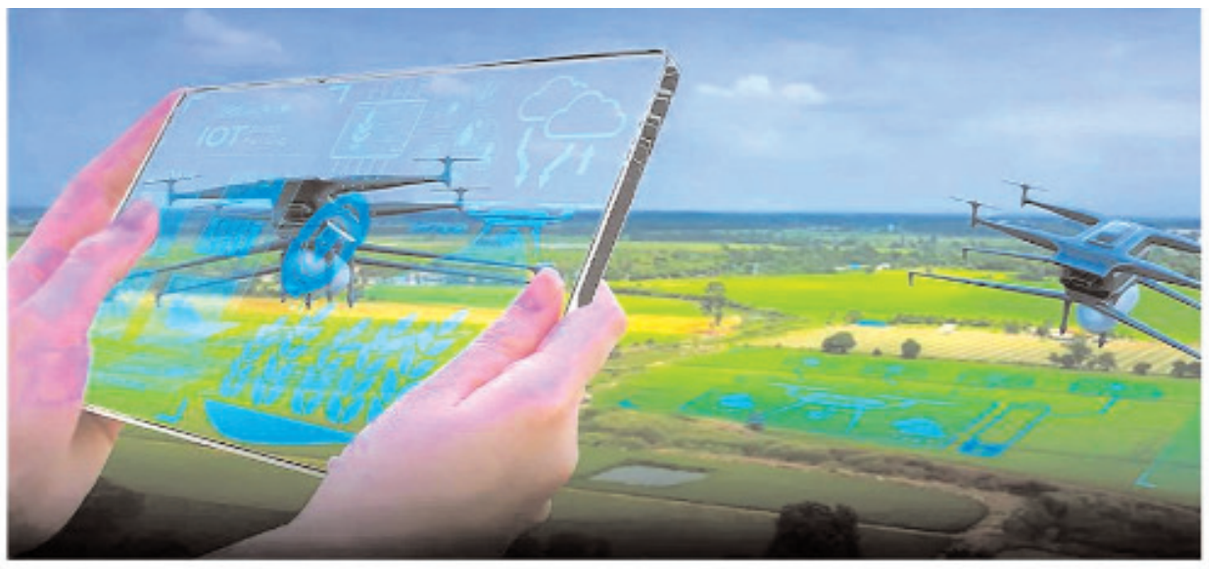
बीज उर्वरक

- रिलीज वर्ष: 2016 (एसवीआरसी)
- उद्गम केंद्र: एआरएस, जालना
- औसत उपज: 16-18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
- परिपक्वता अवधि: 120-135 दिन
- उपयुक्त क्षेत्र: महाराष्ट्र
- विशेष लक्षण: सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
- मुख्य विशेषता: सफेद दानों वाली काबुली किस्म (29 ग्राम प्रति 100 बीज), मुरझान और स्टंट रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी

यह किस्म न केवल दाने के आकार और रंग के कारण बाजार में लोकप्रिय है, बल्कि इसकी रोग सहनशीलता और उपज क्षमता भी किसानों को अच्छा मुनाफा दिला सकती है।

3. गुजरात जूनागढ़ ग्राम 6 (जीजेजी 6) — उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक किस्म
   - रिलीज वर्ष: 2016 (एसवीआरसी)
   - उद्गम केंद्र: जूनागढ़
   - औसत उपज: 16-18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
   - परिपक्वता अवधि: 120-130 दिन
   - उपयुक्त क्षेत्र: गुजरात
   - विशेष लक्षण: सामान्य बुवाई के लिए उपयुक्त
   - मुख्य विशेषता: मुरझान और स्टंट रोगों के प्रति सहिष्णु

गुजरात के किसानों के बीच यह किस्म लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह सामान्य बुवाई में भी बेहतर पैदावार देती है और बीमारियों से सुरक्षित रहती है।



भारत में खेती को बदल रहीं ये आधुनिक तकनीक

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि कैसे सात आधुनिक टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं। खास बात यह है कि इन बदलावों के लिए फोरम ने अपनी रिपोर्ट में भारत की कई केस स्टडी का हवाला दिया है।

भारत की केस स्टडी का रिपोर्ट में हवाला

तकनीक से कृषि में बढ़ेगी उत्पादकता

Agriculture News: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स और उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग सहित सात उभरती टेक्नोलॉजी कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इन सात उभरती टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विजन, एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), CRISPR (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स) और नैनो टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। ये ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करते हुए लचीलापन और उत्पादकता को बढ़ावा देंगी। रोचक बात यह है कि इस रिपोर्ट में भारत की कई केस स्टडी का हवाला दिया गया है।

रिपोर्ट का शीर्षक 'कृषि में गहन-तकनीकी क्रांति को आकार देना' है। इसे उद्योग और शिक्षा जगत, दोनों के हितधारकों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर संकटों के दौर से गुजर रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से आजीविका को खतरा

गांवों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन, जलवायु परिवर्तन की तीव्रता और प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर मिट्टी और जल का तेजी से क्षरण उत्पादकता को खतरे में डाल रहे हैं। इससे कृषि पर निर्भर आजीविका के लिए भी खतरा बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (खाद्य) के अनुसार वर्ष 2050 तक बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया को काफी अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। यह लक्ष्य बढ़ते दबावों को देखते हुए हासिल करना होगा, क्योंकि दुनिया की एक-तिहाई मिट्टी का क्षरण हो चुका है, 71 प्रतिशत एक्वीफर समाप्त हो चुके हैं और औसत किसान की उम्र लगभग 60 वर्ष हो रही है।

टेक्नोलॉजी में मूलभूत बदलाव लाने की क्षमता

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कहा कि इन सात तकनीकी क्षेत्रों में फसलों की खेती, निगरानी, संरक्षण और वितरण के तरीकों में मूलभूत बदलाव लाने की क्षमता है, जिससे पूरे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और लचीलेपन में सुधार होगा। रिपोर्ट में ऑटोनोमस स्वार्म रोबोटिक्स, प्रिसिजन कृषि प्रबंधन, एजेंटिक एआई सिस्टम और कार्बन रिपोर्टिंग जैसे उच्च-प्रभावी उपयोग के मामलों के लिए इन टेक्नोलॉजी की क्षमता पर भी प्रकाश डाला गया है।

सरकारों से तालमेल बनाए रखने का आग्रह

इसमें कई उदाहरण भी दिए गए हैं। मसलन, जलवायु-अनुकूल चावल की किस्में जो 20 प्रतिशत कम उत्सर्जन करती हैं, गन्ने में प्रिसिजन खेती जिससे पैदावार में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुईहै, और सप्लाई चेन जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने और कार्बन वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए रिमोट सेंसिंग के उपयोग को प्रदर्शित किया गया है।

WEF ने गहन तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है जो कृषि प्रणालियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसने सरकारों से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए चुस्त नीतियों और नियामक सैंडबॉक्स को अपनाने का आग्रह किया है।

कृषि पहल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की कृषि पहल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI4AI) की तरफ से जारी की गई है। वर्ष 2021 से AI4AI पहल ने भारत में 895,000 से अधिक किसानों को डिजिटल तकनीक प्रदान की है। AI4AI ने कृषि में टेक्नोलॉजी के परिवर्तनकारी प्रभाव को दिखाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और नागरिक समाज सहित बहु-हितधारक साझेदारियों को बढ़ावा दिया है। भारत में सीखे गए सबक के आधार पर AI4AI ने सऊदी अरब, कोलंबिया और ब्राजील में भी इसी तरह की पहल की अवधारणा का समर्थन किया है। WEF ने कहा कि अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण कई बागवानी फसलों को लगभग 65 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

भारत की केस स्टडी का हवाला

रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा देश में जलवायु-अनुकूल चावल विकसित करने की एक केस स्टडी का हवाला दिया गया है। फसल-सुधार की पारंपरिक विधियों में प्रजनन चक्र लंबा होता है और प्रिसिजन सीमित होता है। इससे उभरते जलवायु और रोग संकट के दबावों से निपटने के लिए किस्मों का विकास धीमा हो जाता है।

इस समस्या से निपटने के लिए ICAR के शोधकर्ताओं ने CRISPR-आधारित जीनोम संपादन का उपयोग करके चावल की दो किस्में विकसित कीं। पहली, DRR 100 ने सूखे, लवणता और जलवायु के दबावों के प्रति सहनशीलता में सुधार किया है। ICAR का दावा है कि इससे उपज में 19 प्रतिशत की वृद्धि और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी हो सकती है। दूसरी किस्म, पूसा डीएसटी चावल 1 लवणीय और क्षारीय मिट्टी में यील्ड में 9.66 से 30.4 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है।

तिलहन की खेती



परिचय

भारत में तिल की खेती पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवम उत्तर प्रदेश में की जाती हैड्ड भारत के कुल उत्पादन 20 प्रतिशत उत्पादन अकेले गुजरात से होता हैड्ड उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यत: बुंदेलखंड के राकर भूमि मे तथा मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, आगरा एवम गैनपुरी में शुद्ध एवम मिश्रित रूप से की जाती हैड्ड तिल की उत्पादकता बहुत ही कम है सघन पद्धतियाँ अपनाकर उत्पादन बढाया जा सकता हैड्ड

जलवायु

तिल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और

भूमि की आवश्यकता पड़ती है

तिल के लिए शीतोषण जलवायु उपयुक्त होती है मुख्यत: बरसात या खरीफ में इसकी खेती की जाती है यह बहुत ही ज्यादा बरसात या सूखा पड़ने पर फसल अच्छी नहीं होती हैड्ड इसके लिए हल्की भूमि तथा दोमट भूमि अच्छी होती हैड्ड यह फसल पी एच 5.5 से 8.2 तक की भूमि में उगाई जा सकती हैड्ड फिर भी यह फसल बलुई दोमट से काली मिट्टी में भी उगाई जाती हैड्ड

प्रजातियां

तिल की जो उन्नतशील प्रजातियाँ है उनके बारे में जाने किसान भाईयो को बताईये उन उन्नतशील प्रजातियों के बारे में

तिल की कई प्रजातियाँ पाई जाती है जैसे की टाईप 4, टाईप12, टाईप13, टाईप78, शेखर, प्रगति, तरुण, कृष्णा, एवम बी 63 प्रजातियाँ हैड्ड

भूमि की तैयारी



फसल की तैयारी के लिए अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए

खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो-तीन जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करके खेत में पाटा लगाकर भुरभुरा बना लेना चाहिएड्ड इसके पश्चात ही बुवाई करनी चाहिएड्ड 80 से 100 कुंतल सड़ी गोबर की खाद को आखिरी जुताई में मिला देना चाहिएड्ड

बीज और बुआई

तिल की फसल में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है और बीज का शोधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करे

एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए तीन से चार किलोग्राम बीज पर्याप्त होता हैड्ड बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिएड्ड

तिल की बुवाई किस समय और किस विधि द्वारा करनी चाहिए

तिल की बुवाई का उचित समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का दूसरा पखवारा माना जाता हैड्ड तिल की बुवाई हल के पीछे लाइन से लाइन 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज को कम गहराई पर करते हैड्ड

पोषण प्रबंधन

फसल में खाद एवम उर्वरको का प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए

उर्वरको का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर करना चाहिएड्ड 80 से 100 कुंतल सड़ी गोबर की खाद खेत तैयारी करते समय आखिरी जुताई में मिला देना चाहिएड्ड इसके साथ ही साथ 30 किलोग्राम नत्रजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिएड्ड रकार तथा भूड भूमि में 15 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिएड्ड नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस, पोटाश एवम गंधक की पूरी मात्रा बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग में तथा नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम निराई-गुड़ाई के समय खड़ी फसल में देना चाहिएड्ड

सिंचाई प्रबंधन

सिंचाई प्रबंधन तिल की फसल में कब होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए इस बारे में बताईये

वर्षा ऋतू की फसल होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती हैड्ड यदि पानी न बरसे तो आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिएड्ड फसल में 50 से 60 प्रतिशत फलत होने पर एक सिंचाई करना आवश्यक हैड्ड यदि पानी न बरसे तो सिंचाई करना आवश्यक होता हैड्ड

निराई-गुडाई

तिल की फसल में निराई-गुडाई कब करनी चाहिए और खरपतवारों के नियंत्रण हेतु क्या उपाय करने चाहिए

किसान भाईयो प्रथम निराई-गुड़ाई बुवाई के 15 से 20 दिन बाद दूसरी 30 से 35 दिन बाद करनी चाहिएड्ड निराई-गुड़ाई करते समय थिनिंग या विरलीकरण करके पौधों के आपस की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर कर देनी चाहिएड्ड खरपतवार नियंत्रण हेतु एलाक्लोर 50 ईसी. 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के बाद दो-तीन दिन के अन्दर प्रयोग करना चाहिएड्ड

रोगों पर नियंत्रण

रोगों पर नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए इस पर जानकारी दे रहे है

इसमे तिल की फिलोड़ी अवम फाईटोप्थोरा झुलसा रोग लगते हैड्ड फिलोड़ी की रोकथाम के लिए बुवाई के समय कूड में 10जी. 15 किलोग्राम या मिथायल-ओ-डिमेटान 25 ईसी 1 लीटर की दर से प्रयोग करना चाहिए तथा फाईटोप्थोरा झुलसा की रोकथाम हेतु 3 किलोग्राम कापर आक्सीक्लोराइड या मैन्कोजेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार दो-तीन बार छिड़काव करना चाहिएड्ड

कीट प्रबंधन

कौन-कौन से कीट तिल की फसल में लग सकते है और उनका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना चाहिए

तिल में पत्ती लपेटक अवम फली बेधक कीट लगते हैड्ड इन कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनालफास 25 ईसी. 1.25 लीटर या मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिएड्ड

कटाई एवं मड़ाई

तिल की फसल की कटाई एवम गड़ाई का सही समय क्या है कब करनी चाहिए

तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे तथा पत्तियां हरा रंग लिए हुए पीली हो जावे तब समझना चाहिए की फसल पककर तैयार हो गयी हैड्ड इसके पश्चात कटाई पेड़ सहित नीचे से करनी चाहिएड्ड कटाई के बाद बण्डल बनाकर खेत में ही जगह जगह पर छोटे-छोटे ढेर में खड़े कर देना चाहिएड्ड जब अच्छी तरह से पौधे सूख जावे तब डंडे छड आदि की सहायता से पौधों को पीटकर या हल्का झाड़कर बीज निकाल लेना चाहिएड्ड

पैदावार

तिल की फसल से लगभग प्रति हेक्टेयर कितनी पैदावार हमें प्राप्त हो जाती है

तकनीकी तरीको से खेती करने पर तिल की पैदावार 7 से 8 कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती हैड्ड

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी आज आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को करेंगे सम्मानित

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को



लखनऊ में आयोजित पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में देशभर के आईटीआई के 52 मेधावी प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित करेंगे। इन सभी ने अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीटी) 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। बयान में कहा गया है कि यह समारोह गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। सम्मानित होने वालों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के 37 प्रशिक्षार्थी (18 पुरुष और 19 महिलाएं) तथा शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के 15 प्रशिक्षार्थी (सात पुरुष और आठ महिलाएं) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस समारोह में उत्तर प्रदेश के छह मेधावी प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री, मंच पर 10 मेधावी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र देंगे।

राहुल का शिकागो में दिए बयान पर भाजपा का तीखा हमला

नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने



शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के बयानों के लिए उन्हें पाकिस्तान का फैन बॉय करार दिया। शिकागो यूनिवर्सिटी में, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक चर्चाओं में भारत की भूमिका अधिक सक्रिय होनी चाहिए। इसके साथ ही चिंता जताई कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत अब केवल एक गौण खिलाड़ी (साइड खिलाड़ी) बनकर रह गया है। गांधी ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का भी जिक्र किया। प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन ने शांति प्रयासों में भारत की भूमिका को स्वीकार किया है, और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी पाबंदियों में छूट दी है।

मंत्री राजभर की पार्टी ने भाजपा से मांगी 36 सीटें : अखिलेश

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने



दावा किया है कि यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भाजपा से 36 सीटों की मांग की है। अखिलेश यादव ने सीटों की सूची भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट मांग रहे हैं। ये लिस्ट नहीं है हारते हुए 'एनडीए' गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है क्योंकि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी दल और बी-पी टीम भी उसी हिसाब से सीटें माँगेंगी। फिर तो भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आई है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी सुभासपा को लेकर सीटों से संबंधित दावा किया था। अब उन्होंने लिस्ट जारी की है। इसके पहले भी सपा ने बीते दिनों एनडीए के सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे।

अभिषेक बनर्जी का न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से



न्यायपालिका के एक वर्ग पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उसे पक्षपाती बताने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी ममता गुट) के डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या न्यायपालिका जनहित की रक्षा करेगी या ताकतवर लोगों के फायदे के लिए गढ़े गए झूठ का साथ देगी। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बांग्ला भाषा में किए गए एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में हाल के दिनों में हुई कुछ कथित घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने इन घटनाओं के जरिए अपने और अपनी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इस साजिश में राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ भाजपा की मिलीभगत थी।

ओडिशा विधानसभा की बैठक 23 नवंबर तक स्थगित

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा



पाढ़ी ने शुक्रवार को चक्रवात अकवान के मद्देनजर सदन की कार्यवाही 23 नवंबर की सुबह तक स्थगित कर दी। चक्रवात ने शुक्रवार को गोपालपुर के पास दस्तक दी। यह फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया गया, जिसके बाद पाढ़ी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विधायक चक्रवात अकवान के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में लोगों की मदद करेंगे। अध्यक्ष ने कहा, सदन की कार्यवाही दो दिन तक स्थगित रहेगी और 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से यह फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा, ''विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि सदन को शुक्रवार के शेष समय और शनिवार के लिए स्थगित करने की आवश्यकता है। रविवार को अवकाश है। ऐसे में विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए दो दिन मिलेंगे। इससे पहले, शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के सदस्य तख्तियां लेकर आसन के करीब पहुंच गए।

यूपी चुनावः कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची पर सपा का मंथन तेज

राम गोपाल यादव संभालेंगे बातचीत की कमान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों—समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस—के बीच सीट-बंटवारे को लेकर हलचल अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। चुनावी रणनीति को धार देने और गठबंधन की गांठ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव को आगे किया है।

खबरों के अनुसार, यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें दो डेटा विशेषज्ञ भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी 23 और 24 नवंबर के बीच कांग्रेस के साथ बातचीत करने वाली है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। कांग्रेस ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर चर्चा हेतु समाजवादी पार्टी (स्क) को 181 विधानसभा क्षेत्रों की एक सूची सौंपी है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित इन 181 सीटों में से 135 सामान्य सीटें हैं, 45 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, और एक सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है।

इस सूची में बागपत, लोनी, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहाबाद, रायबरेली, अमेठी और कानपुर कैंट जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यह सूची अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली स्क को भेज दी गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने की



दिशा में काम कर रही हैं।

इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सीटों का आवंटन इस आधार पर होगा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने की बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। हम हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि कौन सी पार्टी जीतने की स्थिति में है। जिस भी पार्टी के पास किसी सीट को जीतने का बेहतर मौका होगा, उसे वह सीट दे दी जाएगी।

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, स्कऔर कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। सपा ने 347 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे और 111 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल दो सीटें ही जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में, जिन्हें दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने अपनी 62 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने अपनी 17 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार दो हार के बाद, समाजवादी पार्टी अब फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है।

ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस होती तो इस मेज पर बैठते भारत के प्रधानमंत्री

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका, चीन और रूस के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही मेज पर बैठे होते।



राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक की तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते। समझौता करने वाला प्रधानमंत्री इस मेज पर कभी नहीं बैठ सकता।

राहुल गांधी की यह टिप्पणी गुरुवार को चीन, रूस और अमेरिका के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद आई। इस बैठक में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में प्रयास करने, तेल की आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु जोखिमों को कम करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई।

यह बैठक चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। तीनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद जारी घोषणा में वैश्विक मुद्दों पर आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक के बाद राहुल गांधी की विदेश नीति पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार को कहा कि देश को कांग्रेस से विदेश नीति पर किसी तरह के उपदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत ब्रिक्स की सदस्यता खो सकता था और वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ जाता।

भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट चीन को सौंप दी थी। उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध और शर्म अल शेख में पाकिस्तान को लेकर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए उस पर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया।

न्याय पत्र का जिक्र कर जयराम ने मोदी को घेरा, कहा-

कांग्रेस की बातें दोहरा रहे हैं और घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर उन पर और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार और वेतन के मुद्दे पर कांग्रेस की ही बातों को दोहराया, जबकि इन्हीं बातों के लिए उन्होंने पहले विपक्षी पार्टी की आलोचना की थी।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए, सांसद ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए न्याय पत्र हमारा घोषणापत्र था। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस न्याय पत्र में हमने बताया था कि 2014 से वेतन, रोजगार और निजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 के बाद से असमानताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस न्याय पत्र को लेकर हमारी कड़ी आलोचना की थी। उस समय, प्रधानमंत्री खुद को नॉन-बायोलॉजिकल कहते थे। उन्होंने कहा था कि यह न्याय पत्र अर्बन नक्सल सोच से भरा हुआ है। अब वे दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए संपत्ति सृजन करने वालों का अपमान किया है। उनका सम्मान नहीं किया है। कल प्रधानमंत्री ने फिक्की को संबोधित किया। फिक्की के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। वे औद्योगिक जगत की एक प्रमुख हस्ती थे। हम उन्हें सौ वर्षों से जानते हैं। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई थी।

जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घबराए हुए हैं। उनके बोलने के तरीके से यह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री हताश, चिंतित और निराश हैं। उन्होंने संपत्ति सृजन करने वालों पर जिस तरह से



हमला किया, वही आरोप उन्होंने हम पर लगाए थे। उन्होंने वही बातें दोहराईं जो हमने अपने न्याय पत्र में कही थीं। उन्होंने अर्बन नक्सल वाली मानसिकता के साथ उन पर जुबानी हमला किया और उन पर आरोप लगाए।

उन्होंने बताया कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रमेश ने कहा कि इससे देश भर के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को सीधा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, नोटबंदी जैसे आत्मघाती फैसले से अर्थव्यवस्था को पहले ही बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर एक जटिल और उलझा हुआ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) थोप दिया। छोटे व्यवसायों के मालिक आज भी इस व्यवस्था से पैदा हुई मुश्किलों से जूझ रहे हैं।

उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से सवाल किया था कि सरकार द्वारा दी गई टैक्स छूट के बावजूद नौकरियां क्यों नहीं पैदा हुईं और वेतन क्यों नहीं बढ़ा। उन्होंने व्यवसायों को चुनौती दी कि वे उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई क्रय शक्ति का इस्तेमाल अधिक रोजगार पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में करें।

खेल
प्रमुख समाचार

दूसरे दिन न्यूजीलैंड से 209 रन पीछे भारत

वेलिंगटन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच



पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में एक विकेट पर 159 रन बनाए हैं और वह अभी 209 रन पीछे है। भारत को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। स्टंप्स के समय केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वह शतक से चूक गए। यशस्वी ने 89 गेंद पर 16 चौके की मदद से 85 रन की तेज पारी खेली। यशस्वी ने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। यशस्वी ने पहले विकेट के लिए राहुल के साथ 130 रन जोड़े। इसके बाद राहुल ने भी टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी को मैट हेनरी ने विकेटकीपर ब्लंडेल के हाथों कैच कराया। राहुल और यशस्वी ने कुछ मुश्किल क्षणों का सामना किया। भारत ने अपना पहला रन पांचवें ओवर में बनाया जब जायसवाल का कवर ड्राइव शॉट वाइड थर्ड स्लिप के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चला गया। राहुल का भाग्य ने साथ दिया क्योंकि वह काइल जैमीसन की गेंद पर डीआरएस अपील से बच गए, जबकि मैट हेनरी ने उन्हें बिल्कुल सामने गेंद फेंकी थी, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने डीआरएस न लेने का फैसला किया। राहुल और यशस्वी ने जिम्मेदारी से पारी आगे बढ़ाई और शतकीय साझेदारी की। 17 टेस्ट और 30 पारियों बाद भारत ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इससे पहले आखिरी बार नवंबर 2024 में पर्थ में खेले गए टेस्ट में इन दोनों ने 201 रनों की साझेदारी की थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले केएल राहुल ने भी पचासा पूरा किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स करीब 900 अंक उछला, निफ्टी 25800 पर बंद

नई दिल्ली। शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 900 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ 83,919 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी50 भी 280 अंकों के ऊपर जाकर 25800 पर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। विदेशी निवेशकों की ताबड़तोड़ लिवाली, कमजोर अमेरिकी डॉलर और घरेलू बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट ने रुपये और शेयर बाजार दोनों को मजबूती दी। पिछले दो हफ्तों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 84,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया। इधर, बैंकिंग शेयरों में शुक्रवार को सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला, जहां निफ्टी बैंक 1572 अंक यानी 2.49 फीसदी की जबरदस्त उछाल के साथ 64,635.20 पर बंद हुआ। इंडेक्स 62,656.65 पर खुला था और दिन के दौरान 62,598.55 के लो से संभलकर 64,680.80 के हाई तक पहुंच गया।

मंगलवार को बंद रहेंगे बीएसई-एनएसई

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए अगले हफ्ते एक अहम अपडेट सामने आया है। नवंबर 2026 में एक बार फिर घरेलू शेयर बाजार में कारोबार बंद रहने वाला है। मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग नहीं होगी। इस दिन निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। ऐसे में ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए बाजार की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करना जरूरी है। 24 नवंबर को शेयर बाजार के प्रमुख सेगमेंट में सामान्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। इसमें इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) शामिल हैं।

फेयरफैक्स ने आईआईएफएल कैपिटल में बढ़ाई हिस्सेदारी

नई दिल्ली। कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की अगुवाई वाले फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स समूह ने आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज में अपनी कुल हिस्सेदारी बढ़ाकर 44.08 प्रतिशत कर ली है और वह कंपनी का नया प्रवर्तक बन गया है। इस बदलाव के बाद कंपनी में मौजूदा प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी घटकर 11.85 प्रतिशत रह गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि फेयरफैक्स की निवेश इकाई एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स और उसके साथ मिलकर काम करने वाली इकाई एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड ने खुले प्रस्ताव और शेयरों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस तरह 19 नवंबर से एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी का प्रवर्तक बन गया है। यह घटनाक्रम फेयरफैक्स समूह की भारत में निवेश रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

अर्बन कंपनी ने क्यूआईपी से 2,500 करोड़ रुपए जुटाए

नई दिल्ली। घरेलू सेवा मंच अर्बन कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उसने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 2,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने बताया कि उसके क्यूआईपी के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मांग मिली। इस राशि का इस्तेमाल अर्बन कंपनी के इंस्टाहेल्प आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र, विपणन, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार यह निर्गम 16 नवंबर को खुला और 19 नवंबर 2026 को बंद हुआ। निदेशक मंडल की कोष जुटाने वाली समिति ने 19 नवंबर को एक रुपये अंकित मूल्य वाले 16,02,56,410 इक्विटी शेयरों को 156 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर आवंटित करने की मंजूरी दी।

क्वाड बैठक: चीन पर आयात निर्भरता घटाने की चुनौती

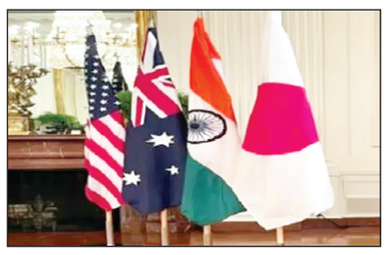
डॉ. जयंती लाल भण्डारी

फिलीपींस की राजधानी मनीला में 17 नवंबर को आयोजित क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) शिखर बैठक में चीन के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए निर्धारित की गई नई आक्रामक रणनीति से जहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों के खिलाफ रणनीतिक संतुलन स्थापित करने का नया दौर आगे बढ़ेगा, वहीं चीन से भारत के आयातों पर निर्भरता में कमी आने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि आगामी 10 महीने में क्वाड देश दुर्लभ खनिजों का उतना उत्पादन कर लेंगे, जितना अभी वे चीन से आयात करते हैं।

वस्तुतः भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में भरोसेमंद विकल्प तैयार करने की राह पर आगे बढ़ेगा। इससे भारत की चीन पर आयात निर्भरता कम हो सकेगी। इस समय जब चीन से होने वाले आयात में अभूतपूर्व और चिंताजनक उछाल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है, तब भारत के द्वारा चीन से आयात नियंत्रण के हर संभव कदम उठाने जरूरी हैं।

हाल ही में 13 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर 2026 में चीन से भारत का आयात लगभग 47 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तमाम सरकारी कोशिशों, मेक इन इंडिया अभियानों और आत्मनिर्भर भारत के नारों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की कई आधारभूत जरूरतें आज भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गहराई से टिकी हुई हैं।

चीन से लगातार बढ़ता व्यापार असंतुलन केवल एक साधारण आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की औद्योगिक स्वायत्तता, तकनीकी सुरक्षा और दीर्घकालिक राष्ट्रीय



संप्रभुता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने चीन द्वारा लगाए गए शुल्क और विभिन्न प्रतिबंधों को भारतीय निर्यात के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जेनेरिक दवाओं और कृषि उत्पादों जैसी भारी संभावनाओं के बावजूद, चीन के गैर-शुल्क और पादप स्वच्छता संबंधी प्रतिबंधों के कारण भारतीय उत्पादों को चीनी बाजार में उचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार इस गंभीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर प्रमुखता से उठा रही है।

स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लगभग 52.5 अरब डॉलर से बढ़कर यह व्यापार घाटा अब 112 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। चीन से आयात में तीव्र वृद्धि इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि हमारे विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की चीन पर निर्भरता कम होने के बजाय और अधिक गहरी और जटिल होती जा रही है।

हमारे लिए चुनौतीपूर्ण यह है कि प्राकृतिक रूप से कच्चे अयस्क (रॉ ओर्स) के विशाल भंडार के बावजूद इनके खनन, जटिल रिफाइनिंग, पृथक्करण (सेपरेशन) और उच्च-स्तरीय चुंबक (मैग्नेट) निर्माण के लिए आवश्यक 'मिडस्ट्रीम' और 'डाउनस्ट्रीम' औद्योगिक क्षमताओं का देश में भारी अभाव है।

आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), विंड टर्बाइन और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों में उपयोग होने वाले परमानेंट मैग्नेट के लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। चूंकि चीन ने इन रणनीतिक खनिजों के प्रसंस्करण और निर्यात पर कड़े नियंत्रण, प्रतिबंध व कोटे लगा रखे हैं, इसलिए भारत को अपने ही घर में मौजूद इस अपार संपदा का सामरिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

रेयर अर्थ के अलावा भी भारत के पास ऐसी कई आंतरिक अनुकूलताएं और सामर्थ्य मौजूद हैं, जिनके बल पर वह चीन पर अपनी इस अवांछित निर्भरता को काफी हद तक खत्म कर सकता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और कुशल तकनीकी इंजीनियरों व युवाओं का सबसे बड़ा समूह है।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने ताम्रध्वज साहू और महंत रामसुंदर दास को भेंट की सोनिया गांधी की किताब



रायपुर (असं)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शुक्रवार को उनके निवास पर पधारे पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू एवं भूतपूर्व विधायक महंत रामसुंदर दास जी को सोनिया गांधी जी की लिखी किताब की प्रति भेंट की।

12 दिसंबर को आयोजित होगी लोक अदालत लंबित ई-चालान प्रकरणों का होगा निराकरण

8 दिसंबर तक कराएं पंजीयन, नहीं तो होगी वैधानिक कार्यवाही

रायपुर। आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में रायपुर शहर में दिनांक 23 जनवरी 2025 से 06 फरवरी 2026 के मध्य जारी लंबित ई-चालान प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु वाहन स्वामी लोक अदालत के पूर्व अर्थात 08 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना अथवा यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी पहुंचकर पंजीयन करा सकते हैं।

पंजीयन हेतु निर्धारित स्थान : यातायात थाना तेलीबांधा, यातायात थाना पचपेड़ी नाका, यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड, यातायात थाना टाटीबंध, यातायात थाना भनपुरी, यातायात थाना पंडरी पुराना बस स्टैंड, यातायात थाना शारदा चौक, यातायात थाना कालीबाड़ी और यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी। वाहन चालक एवं वाहन स्वामी परिवहन विभाग के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल httpss//echallan.parivahan.nic.in/challan/challan-services पर जाकर अपने वाहन का नंबर अथवा चालान विवरण दर्ज कर लंबित चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीसीपी ट्रैफिक्स डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से विशेष अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लंबित ई-चालान प्रकरणों का पंजीयन कराकर लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण कराएं। निर्धारित समय पर चालान का भुगतान एवं निराकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन की सेन्ट्रल कमेटी की बैठक संपन्न

रायपुर। ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज



फेडरेशन की सेन्ट्रल कमेटी की मीटिंग मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित की गई। मीटिंग में 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मीटिंग का उद्घाटन ए.आई.बी.ई.ए. के महासचिव सी. एच. वेंकटाचलन द्वारा किया गया। बैठक में मेघालय अपेक्स बैंक के एम.डी. ओरमोड ई जे नोंगडी एवं जोसफिया वाखर सी.ई.ओ. शिलांग को-ऑप. अर्बन बैंक द्वारा अपने विचार रखे गये। मीटिंग में ए.आई.सी.बी.ई.एफ के महासचिव के.वी.एस. रवि कुमार द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सहकारी बैंकों की वर्तमान परिस्थिति पर विस्तार पूर्वक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं चार बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। मीटिंग के अंत में आभार व्यक्त ए. आई. सी. बी. ई. एफ के उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह आमरे द्वारा किया गया एवं जानकारी दी गई कि आगामी कार्यक्रम चेन्नई व त्रिवेंद्रम सहित उड़ीसा में शीघ्र आयोजित किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ से मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रीय उपमहासचिव एवं छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश व्यास द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारियों को पंजीयक द्वारा नियमविरूद्ध ढंग से वार्षिक इन्क्रीमेंट रोकने, कर्मचारियों के एक्सग्रेशिया को शासन के वित्त विभाग की अनुमति हेतु भेजने संबंधी जानकारी दी गई।

साथ ही अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक के प्रबंध संचालक के वेतन बराबर मानदेय की अनुचित व नियम विरूद्ध मांग जिसका ना तो सहकारी सोसायटी अधिनियम छ.ग. के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष में इसका कोई प्रावधान नहीं होने संबंधी जानकारी दी गई तथा इस बात का भी उल्लेख किया गया कि यदि अपेक्स बैंक में इस तरह का मानदेय देने का प्रावधान किया जाता है तो इसकी मांग जिला सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों में भी की जायेगी जिससे पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी समिति व जिला बैंक व अपेक्स बैंक पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ेगा जो सहकारी आंदोलन को कमजोर बनायेगा।

नर्सिंग की रिक्त सीटों के लिए दूसरे और तीसरे चरण की संयुक्त काउंसिलिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दूसरे और तीसरे (मॉप-अप) चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें शामिल हैं।

इस चरण के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी संस्था और विषय का दोबारा चयन कर सकेंगे। संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने विकल्प दोबारा भरकर लॉक करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रवेश ले चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन का विकल्प भी मिलेगा। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पंजीयन और संस्था का चयन कर सकेंगे।

संयुक्त चरण में शेष रिक्त सीटों के संवर्ग, श्रेणी और नियतांश में परिवर्तन छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 10 और 11 के अनुसार किया जाएगा। समिति ने अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश संबंधी आगामी जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट 222.cgdme.in नियमित रूप से देखने को कहा है।

राजधानी में हवाओं के साथ बारिश, तापमान में गिरावट

कई जिलों में अलर्ट, वर्षा और वज्रपात की चेतावनी





रायपुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में चक्रवाती तूफान अकवान का असर देखने को मिल रहा है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। जिससे राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है और ठिठुरन महसूस की जा रही है।

शुक्रवार सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने से शहर में कुछ जगह लोग अलाव जलाकर आग तापते नजर आए। शुक्रवार को राजधानी में बादल छाए रहे और जगह-जगह रुक-रुककर हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम और ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने रायपुर समेत प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। अलर्ट वाले जिलों में रायपुर के अलावा बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद शामिल हैं। मौसम का मिजाज बदलने और असामयिक बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और धान खरीदी केंद्रों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

ठंडी हवाओं से बढ़ी ठंडक

- रायपुर में गुरुवार रात से ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। इसका असर अगले दिन शुक्रवार को भी देखने को मिला और दिन भर बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश होती रही। वहीं बारिश होने की वजह से जगह-जगह भीड़ और गड्ढों में पानी भरे हुए दिखाई दिए। वहीं, कई स्थानों पर आम नागरिकों के द्वारा अलाव जलाकर ठंडी से बचाव का प्रयास भी किया गया।

देवउठनी पर्व पर बारिश से बिगड़ा मिजाज

देवउठनी के अवसर पर शुक्रवार सुबह से ही बारिश ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया। जिससे व्यापारियों की समस्या बढ़ गई और सड़क पर ही लोग अपनी सामग्री धरे के धरे रह गए, जिससे व्यापार भी काफी प्रभावित रहा। मौसम की मार ने आम नागरिकों से लेकर व्यापार जगत को भी नुकसान पहुंचाया। राजधानी के बाजारों से भीड़ पूरी तरह से नदारद दिखी। जिसका असर व्यापार से लेकर आम नागरिकों तक दिखाई दिया।

मौसम विभाग की चेतावनी: बारिश और बिजली से रहें सतर्क

चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए।

रेलवे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल

कोच में आग और डिरेल होने की स्थिति में बचाव का हुआ जीवंत प्रदर्शन





नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं राज्य आपदा मोचन बल की टीम के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन मरौदा रेलवे स्टेशन में किया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा अपने फ्रंट लाइन स्टाफ, रेल आपदा प्रबंधन टीम एवं स्थानीय नागरिकों को गाड़ियों में होने वाली आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले बचाव कार्य से संबंधित तरीकों को अभ्यास के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने की नियमित प्रक्रिया है, ताकि वे दुर्घटना के समय किए जाने वाले बचाव कार्य के तरीकों को अपनाकर कुशलतापूर्वक राहत कार्य कर सकें।

शुक्रवार को यह अभ्यास प्रदर्शन एनडीआरएफ की बटालियन मुंडाली (कटक) ओडिशा, एसडीआरएफ रायपुर मंडल - संरक्षा विभाग, रेल आपदा प्रबंधन टीम की आपदा राहत टीम तथा सिविल डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से मरौदा में किया गया। उक्त संयुक्त मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ , एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड, ART/ARME टीम एवं रेलवे मेडिकल टीम, वाणिज्य, मैकेनिकल, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल एवं अन्य विभाग मौजूद रहे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन एवं BSP के अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस एवं लोकल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल की उचित व्यवस्था थी। इस प्रदर्शन में कोच के डिरेल होने पर होने वाली स्थितियों को निर्मित किया गया।

सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगने की स्थिति को दर्शाते हुए यह बताया गया कि इस दौरान कैसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए एवं उनकी सहायता की जाए। रेलवे कोच को काट कर यात्रियों को निकालने के नवीन संसाधनों का उपयोग साथ ही आग को बुझाने के विभिन्न तरीकों को भी जीवंत रूप में दिखाया गया।

मेकाहारा में दो दिनों में 48 ऑपरेशन, 18 नवम्बर को 24 और 19 नवम्बर को भी 24 सर्जरी की गई

रायुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) में 18 एवं 19 नवम्बर को मरीजों की सामान्य एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं निरंतर जारी रहीं। अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन दो दिनों में कुल 48 ऑपरेशन किए गए। इनमें 27 नियमित एवं 21 आपातकालीन सर्जरी शामिल हैं। 18 नवम्बर को कुल 24 तथा 19 नवम्बर को भी 24 ऑपरेशन किए गए।

एनेस्थीसिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 18 नवम्बर को विभिन्न ऑपरेशन थिएटरों में 16 नियमित सर्जरी की गईं। इसके अतिरिक्त 8 आपातकालीन सर्जरी भी संपन्न हुईं। इसी प्रकार 19 नवम्बर को 11 नियमित एवं 13 आपातकालीन सर्जरी की गईं। इस तरह दोनों दिनों में नियमित और आपातकालीन मिलाकर कुल 48 ऑपरेशन किए गए। 19 नवम्बर को नियमित ओटी में विभिन्न विभागों की सर्जरी हुई। मेजर ओटी, ईएनटी ओटी, ऑर्थो ओटी, कैंसर ओटी एवं थोराकोस्कोपी ओटी में कुल 11 नियमित ऑपरेशन संपादित किए गए।

अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भी रहीं जारी

एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. जया लालवानी के अनुसार, रूटीन एवं इमरजेंसी सर्जरी के अतिरिक्त एनेस्थीसिया विभाग द्वारा मरीजों की प्री-एनेस्थेटिक चेकअप (पीएसी), आईवी कैनुलेशन, सीईसीटी एवं इंट्यूबेशन जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की गईं। 18 नवम्बर को 10 मरीजों का पीएसी, 9 मरीजों का आईवी कैनुलेशन तथा एक सीईसीटी किया गया। वहीं 19 नवम्बर को 14 मरीजों का पीएसी, 13 मरीजों का आईवी कैनुलेशन, एक सीईसीटी एवं दो मरीजों का इंट्यूबेशन किया गया। इसके अलावा एचडीयू में भर्ती मरीजों की निगरानी एवं उपचार भी नियमित रूप से जारी

24वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ

'सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार' विषय पर 33 जिलों के बाल वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे विचार समाधान



रायपुर। छत्तीसगढ़ के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान की प्रवृत्ति और नवाचार की भावना विकसित करने के उद्देश्य से 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत 24वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुक्रवार को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शुभारंभ हुआ।

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिक अपनी शोध परियोजनाओं और अभिनव विचारों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति एवं निदेशक ओ.पी. व्यास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रशांत कविश्वर शामिल हुए। इस वर्ष बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय 'सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार' निर्धारित किया गया है। इस मुख्य विषय के अंतर्गत पांच उपविषयों पर बाल वैज्ञानिकों द्वारा शोध परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। राज्य के सभी 33 जिलों से कुल 4,228 बाल वैज्ञानिक समूहों के 8,456 बाल वैज्ञानिकों ने पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराया है। अक्टूबर एवं नवम्बर 2026 के दौरान सभी जिलों में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में चयनित प्रत्येक जिले के पांच बाल वैज्ञानिक राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपनी शोध परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

संयम संग्रामोत्सव का शुभारंभ आज, चार मुमुक्षु आत्माओं की वैराग्य भावना की होगी अनुमोदना



रायपुर। आत्मशुद्धि, तप आराधना और संयम साधना के पावन भावों से सुसज्जित तीन दिवसीय 'संयम संग्रामोत्सव' का शुभारंभ 21 नवंबर से होगा।

श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट, रायपुर के तत्वावधान में आयोजित इस आध्यात्मिक महोत्सव के पहले दिन दादाबाड़ी प्रवचन हॉल में शक्रस्तव अभिषेक, बहुमान, पूजा और भक्ति के कार्यक्रम होंगे। शाम को सदर जैन मंदिर में मुमुक्षु आत्माओं द्वारा भव्य आरती की जाएगी। महोत्सव में चार मुमुक्षु आत्माओं की वैराग्य भावना की अनुमोदना की जाएगी। इनमें रायपुर के बालमुमुक्षु निपुण बैद, फिंगेश्वर की राखी चोपड़ा तथा दल्ली राजहरा की दर्शिता नाहटा और राशि नाहटा शामिल हैं। ये मुमुक्षु आत्माएं सांसारिक जीवन से विरक्त होकर संयम और साधना के मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हैं।

महोत्सव के प्रथम दिवस को 'निर्मलता कारक' दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे दादाबाड़ी प्रवचन हॉल में शक्रस्तव अभिषेक एवं बहुमान का कार्यक्रम होगा।

यह आयोजन श्रेणी तप तपस्वी श्रीमती सुमनजी छाजेड़ और मुमुक्षु आत्माओं की अनुमोदना के लिए रखा गया है। इसके साथ पूजा और भक्ति का कार्यक्रम होगा, जिसकी प्रस्तुति मुंबई के मंथन शाह देंगे। कार्यक्रम के पश्चात तपस्वी परिवार की ओर से साधार्मिक वात्सल्य रखा गया है। दिनभर के धार्मिक कार्यक्रमों के बाद शाम 6:30 बजे कोतवाली चौक स्थित जैन स्तम्भ से होते हुए सदर जैन मंदिर पहुंचेंगे जहाँ मुमुक्षु आत्माओं द्वारा भव्य आरती की जाएगी। इस अवसर पर समाजजन और श्रद्धालु मुमुक्षुओं की वैराग्य भावना की अनुमोदना करेंगे।

फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना, मिलेगा बीमा का लाभ

टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं शिकायत, बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों



रायपुर। चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से जिले में हुई असामयिक वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खड़ी एवं कटाई के बाद खेतों तथा खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। साथ ही चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा दावा राशि का लाभ मिल सके।

कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि चक्रवाती तूफान अकवान के कारण जिले में असामयिक वर्षा हुई है। इससे विशेष रूप से धान की कटाई कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल के बारिश में भीगने तथा अधिक नमी के कारण खराब होने की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय-सीमा में देना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों की बीमित फसल को चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा से नुकसान पहुंचा है, वे नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर इसकी सूचना दर्ज कराएं।

समय पर सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 दिनों के भीतर प्रभावित फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा। कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखी गई बीमित धान की फसल, जिसे स्थानीय भाषा में करपा कहा जाता है, के लिए भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। यह प्रावधान फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक लागू होता है।

पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी तत्काल दें जानकारी

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि चक्रवाती तूफान के कारण फसल को अधिक नुकसान होने की स्थिति में वे तत्काल राजस्व विभाग के संबंधित पटवारी तथा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी इसकी जानकारी दें। इसके साथ ही प्रभावित किसान अपनी खड़ी अथवा कटाई के बाद खेतों में रखी फसल की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सुरक्षित रखें। इन तस्वीरों और वीडियो में फसल की वास्तविक स्थिति तथा नुकसान का स्पष्ट विवरण दिखाई देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर क्षति के आकलन में सहायता मिल सके।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.